RNI NO PUNBIL/2014/59416

UTURNTIME.COM

4th Year Anniversary

यूटर्न टाइम

The Good, Bad and Ugly of India

FOLLOW US ON @UTURNTIMENEWS

गुस्ताखी माफ

करती डिजीटल नाक यह, कई अनोखे काम।
ऊपर से इसको कभी, होता नहीं जुकाम।
होता नहीं जुकाम, मगर चढ़ जाता पारा।
गड़बड़ कोई कहीं, सूंघ लेती यह सारा।
कह साहिल कविराय, किसी से यह ना डरती।
अपनी डिजिटल नाक, काम है धांसू करती

- डॉ. राजेन्द्र साहिल

VOL: 11 | ISSUE 64 | WEDNESDAY 18-03-2026 | RS-03 | PAGE-12 | PUBLISHED BY: LUDHIANA | HINDI DAILY NEWSPAPER Visit at : www.uturntime.com

मौलीजागरां में गार्बेज कलेक्टर पर हमले को लेकर उबाल: थाने के बाहर सैकड़ों लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने रविवार तक गिरफ्तारी का दिया आश्वासन

अजीत झा

चंडीगढ़, यूटर्न, 17 मार्च। मौलीजागरां में डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्टर यूनियन के प्रधान धर्मवीर राणा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से वाल्मीकि समाज में भारी रोष फैल गया है। घटना के 11 दिन बाद भी पुलिस कार्रवाई न होने से नाराज समाज के लोगों ने मंगलवार को बड़ी संख्या में मौलीजागरां थाने के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

होली के दिन हुआ था हमला

जानकारी के अनुसार 4 मार्च को होली के दिन धर्मवीर राणा अपने भाई के घर मौलीजागरां विकास नगर में मौजूद थे। इसी दौरान 15 से 20 अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और तेजधार हथियारों से उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में धर्मवीर राणा गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है।

एफआईआर दर्ज, लेकिन गिरफ्तारी नहीं

घटना के बाद शिकायत मिलने पर मौलीजागरां थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। लेकिन 11 दिन बीत जाने के बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से वाल्मीकि समाज में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

पुलिस ने दिया रविवार तक का समय

मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर पहुंचे डीएसपी नॉर्थ-ईस्ट विजय कुमार ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और रविवार तक आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। डीएसपी विजय कुमार के इस आश्वासन के बाद प्रदर्शनकारियों ने फिलहाल अपना धरना समाप्त कर दिया। हालांकि समाज के लोगों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

कई राजनीतिक और सामाजिक नेता पहुंचे

प्रदर्शन में शहर के कई राजनीतिक और सामाजिक नेता भी शामिल हुए। इनमें शहर के पूर्व मेयर कुलदीप कुमार, पूर्व डिप्टी मेयर अनिल कुमार दुबे, आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के महासचिव सन्नी सिंह औलख, वाल्मीकि शोभायात्रा कमेटी के संयोजक समदर्श वेद (जोसफ), कांग्रेस नेता गुरुचरण सिंह, डोर-टू-डोर गार्बेज कलेक्टर यूनियन के चेयरमैन रणवीर सिंह गुग्गी और बिजेंद्र डोलगच सहित कई प्रमुख लोग मौजूद रहे।

थाने के बाहर जुटा वाल्मीकि समाज

मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग नेता गण और महिला सफाई कर्मचारी मौलीजागरां थाने के बाहर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। लोगों ने यह भी मांग उठाई कि मामले में धारा 307 (हत्या के प्रयास) को भी जोड़ा जाए ताकि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके।

मेयर इन एक्शन: जोन-ए के बाहर सड़क पर रेहड़ी-फड़ी, रॉन्ग पार्किंग व अवैध कब्जे हटवाए, चर्चा - तहबाजारी टीम की दुकानदारी हुई बंद

राजदीप सिंह सैनी

लुधियाना/यूटर्न/17 मार्च। लुधियाना कारपोरेशन जोन-ए के बाहर माता रानी मार्केट में रेहड़ी-फड़ी, अवैध कब्जों और रॉन्ग पार्किंग की भरमार है। जिस कारण वहां ट्रैफिक जाम लगा रहता है और राहगीरों को पैदल चलने के लिए जगह तक नहीं मिलती। इन समस्याओं को देखते हुए मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर की और से सख्त एक्शन लिया गया। जिसके चलते मेयर मंगलवार को खुद ही ग्राउंड पर पहुंची। उन्होंने मौके पर तहबाजारी टीम और ट्रैफिक पुलिस को बुला लिया। जिसके बाद तुरंत सड़क पर लगी रेहड़ी फड़ी हटाई गई। इसी के साथ साथ सड़क पर रॉन्ग पार्किंग में लगे वाहन और दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर सामान रखकर किए अवैध कब्जे भी हटवाए गए। वहीं कइयों के चालान किए गए। जबकि मार्केट के सभी दुकानदारों और वाहन चालकों को चेतावनी दी गई है कि अपने व्हीकल्स मल्टीस्टोरी पार्किंग में लगाए। अगर सड़क पर लगे दिखे तो फिर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ साथ मेयर द्वारा तहबाजारी टीम को भी दोबारा कब्जे होने पर प्रशासनिक कार्रवाई करने की वॉर्निंग दी गई है। वहीं मेयर के इस एक्शन के बाद शहर में चर्चा है कि तहबाजारी टीम खुद उक्त रेहड़ियां लगवाती है और कई अज्ञात लोग उनसे अवैध वसूली करते हैं। लेकिन अब तहबाजारी टीम की दुकानदारी बंद होगी।

मेयर की इंस्पेक्टर हांडा को चेतावनी; दोबारा कब्जे हुए तो फिर बदली का मत कहना

जे साडा मत्था ही साफ नहीं, फिर शहर नूं किवें साफ करागें...वहीं इस दौरान मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर ने मंदिर कमेटी के सदस्यों को मौके पर बुलाया और वाहन पार्किंग में लगवाने को कहा। वहीं कमेटी सदस्यों ने बताया कि सफाई कर्मी घंटा घर वाली सड़क पर रोजाना सुबह सफाई करते हैं और सारा कूड़ा मार्केट की तरफ धकेलकर चले जाते हैं। जिस पर मेयर ने सभी सफाई कर्मियों की क्लास लेने की बात कहीं। मेयर ने निगम मुलाजिमों को कहा कि जे साडा मत्था (निगम ऑफिस के आगे) ही साफ नहीं, फिर शहर नूं किवें साफ करागें।

फुटपाथ करवाए जाएंगे तैयार...इस दौरान मेयर द्वारा सभी रेहड़ियां हटवाकर वहां सफाई भी करवाई। इस बीच कई रेहड़ी वाले तो मौके से भाग निकले। मेयर ने कहा कि अब इस सड़क पर न तो रेहड़ी लगने दी जाएगी और न ही रॉन्ग पार्किंग होगी। फुटपाथ दोबारा से तैयार करने के आदेश दे दिए हैं, ताकि पैदल चलने वाले लोग आसानी से चल सके।

वाहन चालकों के चालान, रेहड़ियों पर साधी चुपी...वहीं मेयर इंद्रजीत कौर के एक्शन के दौरान जब तक रेहड़ी-फड़ी और अवैध कब्जों की बात होती रही, तब तक मौके पर मौजूद तहबाजारी टीम के मुलाजिम कुछ बोले नहीं कि रेहड़ियां कैसे और क्यों लगती है। जबकि तहबाजारी मुलाजिम खुद कई बार इन्हें हटा चुके। मगर जैसे ही दुकानों के आगे रॉन्ग पार्किंग की बात आई तो तहबाजारी टीम झट से वाहन चालकों के चालान करने चल पड़ी।

Celebrate your Birthday or Anniversary with UTURN TIME in association with

Hot Breads

0161-4603333, 5012222

2 LUCKY WINNERS WILL GET CAKE WORTH OF ₹1200 EACH

*WINNERS WILL BE DECIDED THROUGH LUCKY DRAW *T&C

FOR MORE DETAILS, CALL: 99882-20063, 98142-95372
janhetaishi@gmail.com, hetaishinews@gmail.com

All rights about Distribution & Offer will be reserved by U-TURN TIME MANAGEMENT Only.

नई आईटीआर डेडलाइन, एसएसटी में बढ़ोतरी, रिवाइज्ड रिटर्न विंडो की समय सीमा बढ़ी

1 अप्रैल से होने वाले इनकम टैक्स के मुख्य बदलावों के बारे में जानें

चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च। भारत के डायरेक्ट टैक्स ढांचे में 1 अप्रैल, 2026 से कई अहम बदलाव लागू होंगे। इसके तहत, इनकम-टैक्स एक्ट, 2025, छह दशक पुराने इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 की जगह ले लेगा। नया कानून आसान भाषा में पेश किया गया है और केंद्रीय बजट 2026 में घोषित प्रस्ताव इसमें वैसे ही बने रहेंगे। टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि इन बदलावों से नियमों का पालन करना आसान होगा, समय सीमा को तर्कसंगत बनाया जाएगा और टैक्स के कुछ ऐसे प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा जो निवेशकों, व्यवसायों और आम लोगों पर असर डालते हैं। इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के तहत एक मुख्य बदलाव टैक्स ईयर (कर वर्ष) की अवधारणा की शुरूआत है। यह इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के तहत 'पिछले वर्ष' और 'असेसमेंट ईयर' के बीच के पुराने अंतर को खत्म कर देगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम का मकसद टैक्स ढांचे को आसान बनाना है, ताकि आय कमाने और उस पर टैक्स देने की अवधि को एक ही शब्दावली के तहत लाया जा सके।

संशोधित तारीखों का ढांचा मोटे तौर पर इस प्रकार होगा

धारा 172 जैसे विशेष प्रावधानों के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए 30 नवंबर ; कंपनियों और उन टैक्सपेयर्स के लिए 31 अक्टूबर जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी है ; ऐसे व्यवसायी या पेशेवर टैक्सपेयर्स के लिए 31 अगस्त जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है ; और बाकी सभी टैक्सपेयर्स के लिए 31 जुलाई। ये संशोधन इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 के तहत टैक्स ईयर 2026-27 से लागू होंगे, जबकि इसी तरह के प्रावधान मौजूदा कानून के तहत असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए 1 मार्च, 2026 से भी प्रभावी होंगे।

फ्यूचर्स और ऑप्शंस पर एसएसटी दरें बढ़ेंगी

सरकार ने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में तेजी से हो रही बढ़ोतरी और फ्यूचर्स और ऑप्शंस सेगमेंट में बढ़ती सट्टेबाजी की गतिविधियों का हवाला देते हुए, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसएसटी) की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी किया है। 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी संशोधित ढांचे के तहत, ऑप्शंस की बिक्री पर एसएसटी दर 0.10 प्रतिशत से बढ़कर 0.15 प्रतिशत हो जाएगी, जबकि ऑप्शंस की बिक्री पर टैक्स, जहां कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, 0.125 प्रतिशत से बढ़कर 0.15 प्रतिशत हो जाएगा। फ्यूचर्स की बिक्री पर एसएसटी 0.02 प्रतिशत से बढ़कर 0.05 प्रतिशत हो जाएगा।

कई लेन-देन पर टीसीएस दरें तर्कसंगत बनाई गईं

बदलावों के एक और सेट में कुछ लेन-देन पर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) दरों को तर्कसंगत बनाना शामिल है। इसका उद्देश्य टैक्स लगाने की प्रक्रिया को आसान बनाना और इसे बदलते आर्थिक और अनुपालन संबंधी विचारों के अनुरूप बनाना है। इंसानों के इस्तेमाल के लिए शराब की बिक्री पर टीसीएस दर 1 प्रतिशत से बढ़कर 2 प्रतिशत हो जाएगी, जबकि तेंदू पत्तों पर यह दर 5 प्रतिशत से घटकर 2 प्रतिशत हो जाएगी। कबाड़ और कोयला, लिग्नाइट और लौह अयस्क जैसे खनिजों की बिक्री पर टीसीएस दर 1 प्रतिशत से बढ़कर 2 प्रतिशत हो जाएगी। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (छफ्र) के तहत शिक्षा या मेडिकल इलाज के लिए 10 लाख रुपये से ज्यादा के रेमिटेंस पर, दर 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दी जाएगी। हालाँकि, दूसरे कामों के लिए किए गए रेमिटेंस पर 20 प्रतिशत टीसीएस लगता रहेगा।

आम लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं

नए कानून के तहत, आम लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब की मौजूदा दरें - चाहे वे पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत हों या रियायती टैक्स व्यवस्था के तहत वैसी ही बनी रहेंगी। इससे व्यक्तिगत टैक्स के बोझ में निरंतरता बनी रहेगी। एक और अहम बदलाव इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की तय तारीखों में संशोधन से जुड़ा है। सरकार ने उन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है जो किसी व्यवसाय या पेशे से जुड़े हैं और जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है। साथ ही, ऐसी फर्मों के पार्टनर्स और कुछ ट्रस्टों के लिए भी यह समय सीमा बढ़ाई जाएगी। संशोधित ढांचे के तहत, इन टैक्सपेयर्स के लिए रिटर्न दाखिल करने की तय तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी जाएगी।

संशोधित रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ाई गई

नया कानून संशोधित रिटर्न फाइल करने की समय सीमा को भी बढ़ाएगा। अभी, टैक्सपेयर संबंधित टैक्स ईयर के खत्म होने के नौ महीने के अंदर या असेसमेंट पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, अपना रिटर्न संशोधित कर सकते हैं। नया ढांचा इस सीमा को टैक्स ईयर के खत्म होने से 12 महीने तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता है। हालांकि, अगर संशोधित रिटर्न नौ महीने के बाद फाइल किया जाता है, तो फीस लगेगी। जहां कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है, वहां 1,000 रुपये की फीस देनी होगी, जबकि जहां इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, वहां 5,000 रुपये की फीस लगेगी।

विदेश टूर पैकेज मामले में भी बदलाव

विदेश टूर पैकेज के मामले में, 10 लाख रुपये तक 5 प्रतिशत टीसीएस और उससे ज्यादा पर 20 प्रतिशत टीसीएस का मौजूदा ढाँचा बदलकर, एक समान 2 प्रतिशत की दर लागू की जाएगी। खास बात यह है कि मोटर गाड़ियों और दूसरी लक्जरी चीजों की बिक्री पर टीसीएस 1 प्रतिशत ही रहेगा, सुरना ने बताया। एम्प्लॉयर द्वारा दिए गए आने-जाने के खर्च पर टैक्स नहीं लगेगा
नया टैक्स कानून एम्प्लॉयर द्वारा घर से ऑफिस आने-जाने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं पर मिलने वाली छूट का दायरा भी बढ़ाता है। पहले, एम्प्लॉयर द्वारा घर और काम की जगह के बीच आने-जाने के लिए दी गई गाड़ी की कीमत को टैक्सेबल सुविधा नहीं माना जाता था।

अवैध हथियारों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, बड़ी वारदात टली

-चरणजीत सिंह चन्न-

जगरांव/यूटर्न/17/मार्च। लुधियाना देहाती पुलिस द्वारा साझा की गई क्राइम रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना सिधवां बेट की पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर किसी संभावित बड़ी वारदात को टाल दिया है। जांच अधिकारी ए.एस.आई. सुखविंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ नहर पुल सिधवां बेट पर गश्त पर थे। गुप्त सूचना के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सिधवां बेट से नकोदर रोड पर छापेमारी कर संदीप सिंह उर्फ सीपा निवासी मधेपुर को अवैध हथियारों के साथ काबू किया गया। कथित आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट (Arms Act) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल को धमकी भरी कॉल, खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले ने दी चेतावनी

अजीत झा

चंडीगढ़, यूटर्न। पंजाबी गायक और अभिनेता गिप्पी ग्रेवाल को एक धमकी भरी कॉल मिलने का मामला सामने आया है। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताते हुए गिप्पी ग्रेवाल को मैसेज का जवाब न देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि इस धमकी भरी कॉल का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

वायरल ऑडियो में कॉल करने वाला व्यक्ति कहता सुनाई दे रहा है कि उसने कुछ दिन पहले भी गिप्पी ग्रेवाल को मैसेज भेजा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। ऑडियो में वह आगे कहता है कि 'मैसेज को इग्नोर मत कर, नहीं तो गोलियां नहीं संभाल पाएगा।' साथ ही उसने यह भी कहा कि उसने 'पाने ऐले' को भी मैसेज छोड़ा है और दोनों से जरूरी बात करनी है। कॉल करने वाला व्यक्ति गिप्पी को धमकाते हुए कहता है कि वह फिल्म बना रहा है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि मोहाली में उसी की फिल्म बनानी पड़ जाए। धमकी भरे इस ऑडियो के सामने आने के बाद पंजाबी म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में भी हलचल मच गई है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस के पास औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है।

Nitin नबीन के राज्यसभा निर्वाचित होने पर वीनू गोयल ने दी बधाई, बताया विकास और जनसेवा का मजबूत चेहरा

लुधियाना/यूटर्न/17 मार्च। भाजपा नेत्री वीनू गोयल ने Nitin नबीन के बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल नबीन के लंबे राजनीतिक सफर और जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है, बल्कि पार्टी के प्रति उनके समर्पण और नेतृत्व क्षमता का भी प्रमाण है।

वीनू गोयल ने अपने संदेश में कहा कि बांकीपुर से पाँच बार विधायक के रूप में सक्रिय भूमिका निभाने वाले श्री नबीन ने

हमेशा जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी है और विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संगठनात्मक स्तर पर भी उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और विश्वास का संचार हुआ है।

उन्होंने आगे कहा कि श्री नबीन का सामाजिक और राजनीतिक अनुभव निश्चित रूप से संसद में राष्ट्रहित और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने में सहायक सिद्ध होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में विकास की नई दिशा तय होगी और देश प्रगति के मार्ग पर और आगे बढ़ेगा। अंत में वीनू गोयल ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे इसी तरह राष्ट्र सेवा में निरंतर अग्रसर रहें।

यूटर्न टाइम
The Good, Bad and Ugly of India

पेज 06 कंवरदीप कौर का कार्यकाल बढ़ा: एक और साल रहेंगी ...

वॉर्ड 91 में पार्क की गंदगी से परेशान हुए लोग, पार्षद पति के सामने बोले - आपको वोटें डाली, फिर खुद क्यों नहीं करवाते काम

विधायक ने लिया संज्ञान, तुरंत करवाई सफाई

राजदीप सिंह सैनी

लुधियाना/यूटर्न/17 मार्च। वॉर्ड 91 के न्यू दीप नगर के पार्क में फैली गंदगी के कारण लोग बेहद परेशान हो गए। लोग इस कुव्यवस्था से इतने नाराज थे कि उन्होंने वॉर्ड 91 की पार्षद तेजिंदर कौर राजा के पति तेजिंदर सिंह राजा के सामने ही अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको वोट डाली है, फिर आप खुद ध्यान रखकर क्यों काम सही से नहीं करवाते हैं। हालांकि लोगों ने यह भी कहा कि यह मामले विधायक चौधरी मदन लाल बग्गा के संज्ञान में आते ही उन्होंने एक्शन लिया। जिसके बाद पार्क की पूर्ण तरीके से सफाई करवाई गई। अब पार्क की ऐसे हालात हैं कि इलाका निवासी नीचे बैठकर खाना भी खा सकते हैं। वहीं मौके पर मौजूद पार्षद पति तेजिंदर सिंह राजा ने कहा कि जब भी मामला उनके ध्यान में आता है, तो तुरंत हल किया जाता है। पार्क की सफाई रुटीन में हो रही है।

वॉर्ड 91 में विकास कार्यों का उद्घाटन करते विधायक मदन लाल बग्गा।

पार्षद को खुद चाहिए सफाई कराना

वहीं इलाका निवासी ने कहा कि पहले पार्क की सफाई होती थी, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए थी। पार्क में चारों तरफ गंदगी फैली रहती थी। विधायक मदन लाल बग्गा के प्रयासों के बाद अब पूरे तरीके से सफाई हुई है। वहीं इस बीच पार्षद पति तेजिंदर सिंह राजा मौके पर पहुंच गए। मीडिया ने लोगों से सवाल किया कि आप पार्षद को शिकायत नहीं करते। आगे से लोगों ने कहा कि हम क्यों करें, हमनें उन्हें वोटें डालकर जिताया है, वह खुद ध्यान क्यों नहीं रखते।

समस्याएं पता चलने पर पहल के आधार पर हुआ काम

वहीं पार्षद पति और आप नेता तेजिंदर सिंह राजा का कहना था कि न्यू दीप नगर में बत्रा अंकल है। जिनकी और से इलाके में जब भी कोई समस्या आती है तो वह उन्हें बताते हैं। जिसके बाद उक्त समस्या को पहल के आधार पर हल किया जाता है। पार्क की सफाई होती है। उन पर आरोप लगाने वाले लोगों का कभी उन्हें फोन नहीं आया।

दो नए पार्क किए जा रहे डेवलप

वहीं विधायक मदन लाल बग्गा ने कहा कि वॉर्ड 91 में दो नए पार्क डेवलप किए जा रहे हैं। वहीं न्यू दीप नगर के पार्क के बारे में उन्हें लोगों ने बताया था, जिसकी पहल के आधार पर सफाई करवाई गई है। पार्क लोगों की मांग मुताबिक डेवलप किए जाएंगे। अगर लोग वहां पर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो जिम लगाए जाएंगे।

अंधेरे में बढ़ रहा अपराध, रिहायशी इलाके की स्ट्रीट लाईटें खराब, प्रशासन से कार्यवाही की मांग

मिलन

लुधियाना/यूटर्न/17 मार्च। महानगर के बहादुरके रोड़ स्थित न्यू दाना मंडी रिहायशी कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटों की भारी कमी के कारण क्षेत्र के लोग गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कॉलोनी के कई हिस्सों में या तो स्ट्रीट लाइटें लगी ही नहीं हैं या फिर जो लगी हैं उनमें से कई लंबे समय से खराब पड़ी हैं, जिससे रात के समय पूरा इलाका अंधेरे में डूबा रहता है। स्थानीय निवासियों के अनुसार पिछले कुछ महीनों के दौरान इलाके में चोरी और छीना-झपटी जैसी घटनाएं

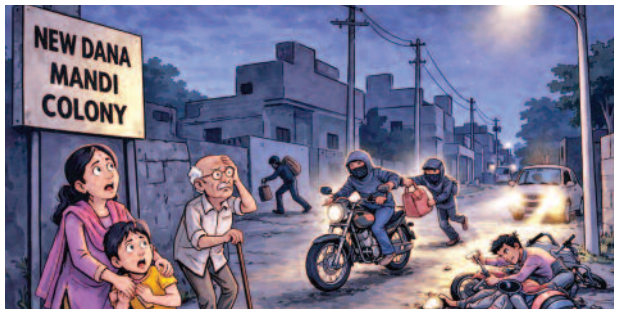

भी सामने आ चुकी हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्व आसानी से वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। इसके अलावा, पर्याप्त रोशनी न होने के कारण रात के समय छोटे-मोटे सड़क हादसे होने का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि वाहन चालकों और पैदल चलने वाले लोगों को सड़क ठीक से दिखाई नहीं देती।

रात के समय घर से निकलना हुआ मुश्किल

निवासियों का कहना है कि सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को होती है, जिन्हें रात के समय बाहर निकलने में असुरक्षा महसूस होती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि कॉलोनी में तुरंत सर्वे करवाकर जहां-जहां जरूरत है वहां नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएं और खराब लाइटों को जल्द ठीक किया जाए, ताकि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके।

मेडिकल स्टोर पर बेची जा रही थी नशीली दवाइयां, पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार

लुधियाना/यूटर्न/17 मार्च। सिविल सिटी इलाके में पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर पर रेड की। जहां से भारी संख्या में प्रतिबंधित

दवाइयों का जखीरा बरामद हुआ। जिसमें कुल 2376 नशीली गोलियां/कैप्सूल बरामद हुई हैं। थाना हैबोवाल की पुलिस ने सिविल सिटी के राजीव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर नवदीप सिंह संधू ने बताया कि पुलिस पार्टी गश्त के दौरान सिविल सिटी चंद्र नगर और हरगोविंद नगर इलाके में मौजूद मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच पुलिस को खास सूचना मिली कि लाइफ मेडिकेयर नामक मेडिकल स्टोर पर सरेआम नशीली गोलियां बेची जा रही हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए चंद्र नगर स्थित उक्त मेडिकल स्टोर पर रेड की। इस दौरान भारी मात्रा में दवाइयां बरामद हुई और आरोपी राजीव कुमार को काबू किया गया।

दो एक्टिवा की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर, एक युवक की मौत, दोस्त जख्मी

लुधियाना/यूटर्न/17 मार्च। न्यू हरगोविंद नगर में दो एक्टिवा की आमने-सामने टक्कर हो गई। जिस कारण दो युवक गंभीर रुप से जख्मी हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। जहां पर एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे का इलाज जारी है। मृतक की पहचान जमालपुर निवासी 33 वर्षीय जय करण उर्फ बबलू के रूप में हुई है। इस हादसे में बबलू का दोस्त भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मामले की सूचना मिलने पर थाना डिवीजन नंबर तीन की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस मामले की जांच कर रही ह। जानकारी के अनुसार जय करण अपनी माता की चुन्नियों की दुकान के लिए एक्टिवा पर सवार होकर दोस्त के साथ सामान लेकर निकला था। जब वह न्यू हरगोविंद नगर के पास पहुँचा तो सामने से आ रही एक तेज रफ्तार एक्टिवा ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। परिवार मुताबिक जय करण शादीशुदा था और अपने पीछे पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा छोड़ गया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

नशीली गोलियों के साथ तस्कर किया काबू

-चरणजीत सिंह चन्न-

जगरांव/यूटर्न/17/मार्च। लुधियाना देहाती पुलिस द्वारा साझा की गई क्राइम रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नशों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत थाना सदर रायकोट की पुलिस ने एक व्यक्ति को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना सदर रायकोट के जांच अधिकारी एस.आई. हरप्रीत सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर बलवीर सिंह उर्फ निक्का निवासी शाहजहांपुर को 10 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। कथित आरोपी के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज कर अगली कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सदन से कांग्रेस के वॉकआउट पर मुख्यमंत्री का तंज, बोले– विपक्ष गैर जिम्मेदार

चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक सदन में झूठे आरोप लगाकर वॉकआउट कर जाते हैं और यह उनकी पुरानी प्रवृत्ति रही है। मुख्यमंत्री ने शायराना अंदाज में कहा कि ह्लजो अपने आप को नहीं संभाल सकते, वो घर को क्या संभालेंगे।ह्व मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वे केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए बजट की निराधार आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बजट को गंभीरता से पढ़ा ही नहीं, इसलिए वे प्रदेश के विकास और योजनाओं पर सार्थक चर्चा नहीं कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि

हरियाणा के करोड़ों लोग विधानसभा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन विपक्ष का गैरजिम्मेदाराना रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। मुख्यमंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ह्लजो खुद चल नहीं पाते रास्तों पर, अक्सर वही मंजिलों पर सवाल करते हैं।ह्व बजट पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि यह उनका दूसरा बजट है, जो करीब 5 हजार सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. रघुबीर कादियान द्वारा बजट भाषण की अवधि पर उठाए सवालों को भी खारिज किया। राज्यसभा चुनाव को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विपक्ष को घेरा और कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने पर सवाल उठाना गलत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने प्री-बजट बैठकों में किसानों की भागीदारी पर विपक्ष के आरोपों को भी निराधार बताया और कहा कि किसान, मजदूर, उद्योग और हर वर्ग की भागीदारी से यह जनहितकारी बजट तैयार किया गया है।

पानीपत में स्थापित की जा रही देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना

चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च। हरियाणा सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाने की तैयारी में है। इस दिशा में भारतीय तेल निगम लिमिटेड (IOC) द्वारा पानीपत में 10,000 टन प्रति वर्ष क्षमता की देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना पीपीपी मॉडल पर स्थापित की जा रही है। इस परियोजना का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक इसे शुरू करना है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस परियोजना की प्रगति और बिजली आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई। इस

परियोजना के तहत पानीपत रिफाइनरी को ग्रीन हाइड्रोजन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को बल मिलेगा और नरेन्द्र मोदी के पंचामृत संकल्पों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य की नई औद्योगिक नीति में ग्रीन हाइड्रोजन को प्राथमिक (थ्रस्ट) सेक्टर के रूप में शामिल किया जा रहा है। इस परियोजना से रिफाइनिंग और इस्पात जैसे उच्च प्रदूषण वाले उद्योगों के डीकाबोर्नाइजेशन में मदद मिलेगी, जिससे हरियाणा लो-कार्बन रिफाइनिंग और ग्रीन स्टील उत्पादन का प्रमुख केंद्र बन सकता है।इसके अलावा, यह परियोजना निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। अनुमान है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्षमता बढ़ने पर राज्य में करीब 40,000 प्रत्यक्ष और 1.2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो सकते हैं। यह पहल हरियाणा की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ग्रीन ऊर्जा आधारित विकास के विजन को भी आगे बढ़ाएगी।

चंडीगढ़ में जल्द लागू होगा 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' एक्ट, टरटए को मिलेगी बड़ी राहत

चंडीगढ़, यूटर्न, 17 मार्च। शहर में कारोबार को बढ़ावा देने और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए यूटी प्रशासन जल्द इज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट लागू करने की तैयारी में है। पंजाब की तर्ज पर लाए जा रहे इस कानून से विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार एक्ट का मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसे अगले महीने लागू किया जा सकता है। इसके लागू होने के बाद उद्योगों, व्यापारियों और स्टार्टअप्स को लाइसेंस, अनुमतियों और अन्य सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी से काफी हद तक राहत मिलेगी।

तय समय सीमा में मिलेगी मंजूरी

प्रस्तावित एक्ट के तहत व्यापार शुरू करने, भवन अनुमति लेने, प्रदूषण से संबंधित मंजूरी, बिजली और पानी के कनेक्शन जैसी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। साथ ही तय समय सीमा के भीतर सेवाएं उपलब्ध कराना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होगी। नई व्यवस्था में एमएसएमई

इकाइयों को सेल्फ-डिक्लेरेशन के आधार पर 'सर्टिफिकेट ऑफ इन-प्रिंसिपल अप्रूवल' जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र करीब तीन वर्ष छह माह तक मान्य रहेगा और इस दौरान उद्यमियों को कई तरह की नियामकीय मंजूरियों और नियमित निरीक्षणों से छूट मिलेगी।

'डीरेगुलेशन 2.0' कार्यक्रम के तहत होंगे सुधार

यूटी प्रशासन इस एक्ट को 'डीरेगुलेशन 2.0' नामक व्यापक सुधार कार्यक्रम के साथ लागू करेगा। इसके तहत भूमि उपयोग, निर्माण अनुमति, बिजली-पानी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं से जुड़े कई नियमों को सरल बनाया जाएगा। यह सुधार मार्च से सितंबर 2026 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाने की योजना है।

सीएलयू की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव

प्रशासन ने चेंज ऑफ लैंड यूज (CLU) की अनिवार्यता खत्म करने का भी प्रस्ताव रखा है। इससे जमीन मालिकों और किसानों को लंबी प्रक्रियाओं से राहत मिल सकती है। इसके साथ ही भूमि उपयोग योजना में ह्यपरमिटेड अनटिल प्रोहिबिटेडह्व सिद्धांत अपनाने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे मास्टर प्लान बनने तक भी निर्माण संबंधी अनुमतियां मिल सकेंगी।

बिल्डिंग परमिट और लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी आसान

आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं को गति देने के लिए बिल्डिंग परमिट की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। अग्नि सुरक्षा मानकों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार तार्किक बनाने की योजना है, ताकि बिल्डरों और संपत्ति मालिकों को मंजूरी जल्दी मिल सके।

ढाई लाख एकड़ में सरसों की खेती, महेंद्रगढ़ के किसान इस बार खुशहाल

हरियाणा/यूटर्न/17 मार्च।दक्षिणी हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे महेंद्रगढ़ जिले के किसानों का मुख्य व्यवसाय खेती बड़ी है इस बार यहां के किसानों ने प्रमुख तौर पर सरसों की फसल की बिजाई की थी और अब फसल काटकर मंडी में आने के लिए तैयार है सरसों की अच्छी पैदावार को लेकर किसानों के चेहरों पर अच्छी रौनक देखी जा रही है तो वही मंडी में किसानों की व्यवस्था को लेकर मार्केट कमेटी ने भी अपनी पूरी व्यवस्थाएं करली है। खेतों में लहराने वाली सरसों की फसल की कटाई का काम पूरा हो चुका है किसान खेतों में इस समय अपनी सरसों की फसल निकालने में लगा है और यह फसल मंडी में आने के लिए तैयार है मंडियों में फसल की बिक्री और किसानों के बैठने की व्यवस्था को लेकर मार्केट कमेटी ने तमाम व्यवस्थाएं पूरी करली है नारनौल मार्केट कमेटी की सचिव नुकूल यादव के अनुसार इस बार महेंद्रगढ़ जिले में सरसों की बिजाई ढाई लाख एकड़ में की गई थी जबकि 84 हजार किसानों ने फसल का अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है सचिव के अनुसार मंडियों में सरसों खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है नारनौल मंडी में एक लाख कट्टे रखने की पूरी तरह से व्यवस्था है जबकि किसानों के बैठने और उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है अनेक मंडियों में अटल कैंटीन की भी व्यवस्था है। सरसों की अच्छी पैदावार को लेकर यहां का किसान काफी खुश नजर आ रहा है किसानों के अनुसार इस बार पिछले साल की तुलना में अच्छी पैदावार हुई है फसल की कटाई जारी है और अब यह फसल मंडी में ले जाकर किसान बेचेगा किसान खेतों में इस समय अपनी सरसों की फसल को निकलने में लगा है ताकि सरसों की फसल को सुखाकर मंडी में बेचने के लिए ले जाया जा सके।

नारनौल में छापेमारी: होटल-ढाबों से जब्त हुए घरेलू गैस सिलेंडर

हरियाणा/यूटर्न/17 मार्च। नारनौल के नांगल चौधरी में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर फूड सप्लाई विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान कई होटल, ढाबों और रेस्टोरेंटों पर कार्रवाई की गई, जहां घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल पाया गया। यह छापेमारी नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर सचिन और सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में की गई। टीम ने मौके से कई घरेलू सिलेंडर बरामद किए, जिन्हें जब्त कर संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि घरेलू सिलेंडरों का उपयोग केवल घरेलू कामों के लिए ही किया जाना चाहिए, जबकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में केवल कमर्शियल सिलेंडरों का ही इस्तेमाल होना चाहिए। विभाग के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट में घरेलू सिलेंडरों का उपयोग पाया जाता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, इस प्रकार की छापेमारी आगे भी लगातार जारी रहेगी।

यूटर्न टाइम
The Good, Bad and Ugly of India

पेज 12 क्या ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी रात भर...

हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 राज्यसभा सीट मिली

चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च। हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए कड़े मुकाबले वाले चुनाव में, सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मंगलवार को 1-1 सीट पर जीत का दावा किया। इस चुनाव में आईएनएलडी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। वोटों की गिनती पूरी होने के बाद, देर रात 1:30 बजे के बाद पार्टियों द्वारा किए गए दावों के अनुसार, बीजेपी के पूर्व सांसद संजय भाटिया और कांग्रेस के दलित कार्यकर्ता करमवीर बौद्ध ने वरीयता वोटों के जरिए चुनाव जीता। नतीजों की आधिकारिक घोषणा का अभी भी इंतजार है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पार्टी के चार वोट अमान्य घोषित कर दिए गए, जबकि उसके पांच विधायकों ने 'क्रॉस-वोटिंग' की। इसके चलते महासचिव बीके हरिप्रसाद ने घोषणा की कि इन विधायकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह साफ है कि कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने क्रॉस-वोटिंग की, लेकिन पार्टी लाइन का उल्लंघन करने वाले चार अन्य विधायकों के नाम अभी सामने नहीं आए हैं। वोट की गोपनीयता के उल्लंघन की तीन शिकायतों में से, एक वोट (कांग्रेस विधायक परमवीर सिंह का) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया। चुनाव आयोग से जवाब मिलने में हुई देरी के कारण वोटों की गिनती पांच घंटे से भी ज्यादा समय तक रुकी रही।

कांग्रेस के अंदरूनी कलह का मुद्दा बनाने का प्रयास

इस बीच, बीजेपी ने कांग्रेस के अंदरूनी कलह को मुद्दा बनाने की कोशिश की, जिसके चलते क्रॉस-वोटिंग हुई थी। ह्लयह चुनाव बहुत ही दिलचस्प था। कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने उन्हें हिमाचल प्रदेश भेज दिया। वे हर घंटे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजते रहे। उनके वरिष्ठ नेता, जिनमें प्रभारी महासचिव भी शामिल थे, पोलिंग एजेंट बन गए,ह्व उट नायब सिंह सैनी ने कहा। उन्होंने आईएनएलडी पर भी तंज कसा कि उसने वोटिंग से दूर रहकर परोक्ष रूप से कांग्रेस की मदद की। सीएम ने कहा कि अगर आईएनएलडी बीजेपी का समर्थन नहीं करना चाहती थी, तो वह निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर सकती थी। लेकिन, वोटिंग से दूर रहने का फैसला करके उसने कांग्रेस की मदद की और उसकी बी टीम बन गई।

बीजेपी व कांग्रेस एक-एक सीट जीतेंगी

हालांकि, यह व्यापक रूप से उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा विधानसभा में अपनी ताकत के आधार पर बीजेपी और कांग्रेस, दोनों एक-एक सीट जीतेंगी, लेकिन नन्दल के आखिरी दिन निर्दलीय नामांकन ने इस मुकाबले में एक नया मोड़ ला दिया। उन्हें तीन निर्दलीय विधायकों और सात बीजेपी विधायकों का समर्थन मिला, जिससे वे राज्यसभा नामांकन दाखिल करने के लिए जरूरी कम से कम 10 प्रस्तावकों की शर्त पूरी कर पाए। अपने विधायकों को ह्यतोड़े जानेह्ल से बचाने के लिए, कांग्रेस ने अपने 31 विधायकों को हिमाचल प्रदेश के एक रिसॉर्ट में भेज दिया था, पहले शिमला और फिर कसौली और उसके बाद उन्हें एक बस में चंडीगढ़ लाया गया।

सतीश नांदल कम अंतर से हारे

बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए। खेल मंत्री गौरव गौतम ने दावा किया कि नांदल सिर्फ तीन वोटों के अंतर से हारे और कहा कि वह जीत के बेहद करीब थे।

उन्होंने आगे कहा कि अगर आईएनएलडी ने वोट दिया होता, तो नतीजे कुछ और हो सकते थे। वोटों की गिनती की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद, दोनों पार्टियों के नेताओं ने घोषणा की कि उनके-अपने उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं।

हरियाणा राज्यसभा चुनाव के नतीजे

विधानसभा की कुल संख्या : 90
वोटिंग से दूर रहे : 2 आईएनएलडी विधायक
प्रभावी संख्या : 88

रद्द हुए वोट

कांग्रेस : 4
बीजेपी : 1
अब प्रभावी संख्या : 83
बीजेपी उम्मीदवार : 28 वोट
कांग्रेस उम्मीदवार : 28 वोट
निर्दलीय उम्मीदवार (बीजेपी समर्थित) : 27 वोट
क्रॉस-वोटिंग : 5 कांग्रेस विधायक

बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप

हरिप्रसाद ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह कांग्रेस के वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने यह भी कहा कि क्रॉस-वोटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, ₹जब 'हॉर्स-ट्रेडिंग' (विधायकों की खरीद-फरोख्त) की बात आई, तो बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कांग्रेस नेता अपनी जमीन पर डटे रहे। बीजेपी नेता तो हमारा पीछा करते हुए हिमाचल प्रदेश तक पहुँच गए थे। हालांकि, उनकी ऐसी सभी कोशिशें नाकाम कर दी गईं। उन्होंने जीत का श्रेय प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दिया।

हरियाणा राज्यसभा चुनाव: क्रॉस-वोटिंग करने वाले विधायकों को कांग्रेस देगी कारण बताओ नोटिस

चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च। कांग्रेस अपने उन विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी जिन्होंने क्रॉस-वोटिंग की थी। वहीं, पार्टी ने राज्यसभा की एक सीट जीतने के बाद राहत की सांस ली है, भले ही बीजेपी समर्थित एक निर्दलीय विधायक ने चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि क्रॉस-वोटिंग करने वालों में दो मुस्लिम विधायक, दो महिला विधायक और एक आरक्षित सीट से विधायक शामिल थे; ये सभी पार्टी के भीतर मौजूद दो मुख्य गुटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। चुनाव में जिन दो सीटों पर मुकाबला हुआ, उनमें से बीजेपी के

आधिकारिक उम्मीदवार और पूर्व सांसद संजय भाटिया की जीत पक्की मानी जा रही थी। हालांकि, निर्दलीय उम्मीदवार के मैदान में उतरने के बाद कांग्रेस की स्थिति अनिश्चित बनी हुई थी।

पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए...राज्य के प्रभारी महासचिव बी.के. हरिप्रसाद ने कहा, उन्हें राज्यसभा चुनाव में अपने आचरण के लिए पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कारण बताओ नोटिस जल्द ही जारी किए जाएंगे, और उनसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने की उम्मीद की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद, पार्टी ने कांग्रेस विधायकों को रिश्वत की पेशकश किए जाने के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत पर आगे कार्रवाई न करने का फैसला किया है।

विधानसभा भवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसकी वास्तुकला और निर्माण से जुड़े पहलुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की

चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च। हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च और गरिमामयी मंच है, जहां जनहित से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता और अनुशासन के साथ चर्चा होती है। उन्होंने बताया कि बजट सत्र विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दौरान प्रदेश की आर्थिक दिशा, विकास योजनाएं और नीतिगत फैसले तय किए जाते हैं। मंत्री गंगवा चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर बरवाला विधानसभा क्षेत्र से आए पत्रकारों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान पत्रकारों ने विधानसभा की कार्यवाही को नजदीक से देखा और प्रश्नकाल, शून्यकाल सहित विभिन्न मुद्दों पर होने वाली चचाओं को समझा। पत्रकारों ने विधानसभा भवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वास्तुकला के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं और आधुनिक वास्तुकला का प्रतीक बताया। प्रतिनिधिमंडल ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही को करीब से देखना उनके लिए ज्ञानवर्धक रहा और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बेहतर समझने का अवसर मिला। बाद में पत्रकारों ने मंत्री रणबीर गंगवा से शिष्टाचार भेंट की, जहां क्षेत्र के विकास कार्यों और परियोजनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने आश्वस्त किया कि बरवाला क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के अंत में मंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

अमित शाह की मोगा रैली से बदली पंजाब की सियासी हवाएं, धर्म परिवर्तन पर सख्त कानून की जरूरत : बिक्रम सिंह सिद्धू

लुधियाना, यूटर्न, 16 मार्च। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पंजाब स्टेट एग्जीक्यूटिव सदस्य बिक्रम सिंह सिद्धू ने कहा कि 14 मार्च को मोगा में आयोजित बदलाव रैली ने पंजाब की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि इस रैली में उमड़ी भीड़ ने यह साफ संकेत दे दिया है कि राज्य की जनता अब बदलाव चाहती है और भाजपा की नीतियों पर भरोसा जता रही है। मीडिया से बातचीत करते हुए सिद्धू ने कहा कि रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि यदि 2027 में पंजाब में भाजपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून लाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में पंजाब के कई गांवों में बड़े स्तर पर धर्म परिवर्तन की घटनाएं सामने आ रही हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय हैं। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति भी लगातार बिगड़ रही है। दिनदहाड़े हत्याएं, लूटपाट, गैंगस्टर गतिविधियां, रेत और लैंड माफिया तथा भ्रष्टाचार के मामलों से आम लोग परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है और राज्य में नशे की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा पंजाब में भ्रष्टाचार और अराजकता के खिलाफ मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। सिद्धू के अनुसार मोगा रैली में वेस्ट लुधियाना से उनके नेतृत्व में करीब 50 बसों और 40 कारों का काफिला शामिल हुआ, जिससे कार्यकताओं का उत्साह साफ दिखाई दिया। उन्होंने दावा किया कि यह रैली पंजाब में राजनीतिक बदलाव का बिगुल साबित होगी।

मंत्री की गूढ़ती से निगम ने बदली परंपरा: ठेकेदारों को बिना 'परसेंटेज' मिली करोड़ों की पेमेंट

ठेकेदारों ने निगम कमिश्नर से मुलाकात कर सुनाया दुखड़ा , जताया आभार

लुधियाना, यूटर्न, 17 मार्च। तीन साल के लम्बे समय बाद सोमवार को निगम द्वारा 55 ठेकेदारों को जारी की गई लगभग 18 करोड़ रु की पेमेंट चर्चा का विषय बन गई। जिसकी मुख्य वजह इतनी बड़ी पेमेंट का बिना किसी कमीशन, घूसखोरी एवं कट के रिलीज होना है। चचाओं की माने तो करीब तीन साल बाद ऐसा इतिफाक हुआ है जब ठेकेदारों को बिना किसी शोषण पेमेंट का भुगतान हुआ है। इसी के चलते मंगलवार को इ&फ और टउ लुधियाना कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के पधादिकारियों ने निगम कार्यालय पहुंच कमिश्नर नीरू कत्याल से मुलाकात कर उनका आभार जताया। इनमें तविंदर पाल सिंह मिंटू ,गुरविंदर सिंह ,वरिंदर सिंह, हरमिंदर सिंह, अजय जिंदल ,अरविंदर पाल सिंह हीरो,राकेश कुमार शामिल रहे। चचाओं अनुसार मीटिंग दौरान ठेकेदारों ने कमिश्नर कत्याल को पिछली समय हुए शोषण का दुखड़ा भी सुनाया।

जिसमें कही सफेद पोशों की पोल भी खुलने के संकेत है। गौरतलब है की पिछले लम्बे समय से निगम में कमीशन एवं घूसखोरी के किस्से किसी से छिपे नहीं है खोरी ऐसे में बिना किसी % ठेकेदारों को इतनी बड़ी पेमेंट रिलीज होने से अच्छे छाचों की नीदें हराम होटी प्रतीत हो रही है। उधर बिना कमीशन और शोषण के पेमेंट रिलीज होने से ठेकेदारों में खुशी का माहौल है। ठेकेदारों में चर्चा है की ऐसा केवल लोकल बॉडी मंत्री संजीव अरोड़ा और निगम कमिश्नर नीरू कत्याल के कारण ही संभव हो पाया है

ये रह चुके है निगम कमिश्नर...चर्चाओं की माने तो पिछली पंजाब सरकार के कार्यकाल से निगम में कमीशनिंग और घुसखोरी ने जोर पकड़ा।

कंवरदीप कौर का कार्यकाल बढ़ा: एक और साल रहेंगी चंडीगढ़ की एसएसपी

चंडीगढ़/यूटर्न/ 16 मार्च। 2013 बैच की आईपीएस अधिकारी कंवरदीप कौर का चंडीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के रूप में कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने उनकी इंटर-कैडर डेपुटेशन अवधि में विस्तार को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा 16 मार्च को जारी आदेश के अनुसार गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कंवरदीप कौर की पंजाब कैडर से एजीएमयूटी कैडर (चंडीगढ़) में डेपुटेशन अवधि को 8 मार्च के बाद एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

कंवरदीप कौर ने 9 मार्च 2023 को चंडीगढ़ के एसएसपी के रूप में कार्यभार संभाला था। प्रारंभिक आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए की गई थी, लेकिन अब नए फैसले के तहत वह अतिरिक्त एक वर्ष तक इस पद पर बनी रहेंगी।

चंडीगढ़ की दूसरी महिला एसएसपी

कंवरदीप कौर चंडीगढ़ की दूसरी महिला एसएसपी हैं। उनसे पहले नीलांबरी विजय जगदले वर्ष 2017 से 2020 तक इस पद पर रह चुकी हैं।

कई अहम मामलों की निगरानी

अपने कार्यकाल के दौरान कंवरदीप कौर ने कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामलों की निगरानी की। इनमें एक एमबीए छात्रा के 15 साल पुराने दुष्कर्म और हत्या मामले की जांच भी शामिल रही, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं एसएसपी ने की थी।

ट्रांसपोर्ट एरिया की समस्याओं को लेकर राज्यपाल कटारिया से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात

चंडीगढ़/यूटर्न/ 16 मार्च। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से ट्रांसपोर्ट एरिया से जुड़े प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को उनके समक्ष रखा। इस दौरान राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुनते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल में प्रधान जसबीर सिंह, के.के. अबरोल, तरसेम पूरी, बलदीप सिंह और जीत राम चौधरी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने ट्रांसपोर्ट एरिया में व्यापारियों और कामगारों को आ रही विभिन्न दिक्कतों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराया।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्य पवन शर्मा ने बताया कि मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने ट्रांसपोर्ट एरिया में चल रहे विकास कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से फोन पर बात कर कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए। राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि ट्रांसपोर्ट एरिया से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिल सके।

तेज रफ्तार वोल्वो बस ने कार को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे सवार

सिंहपुरा चौक के पास देर रात हादसा, दरवाजे क्षतिग्रस्त; चालकों में बहस

लुधियाना, यूटर्न 17 मार्च। स्थानीय ड्रग विभाग ने एक विशेष गुप्त सूचना के आधार पर न्यू चंदर नगर, लुधियाना स्थित लाइफ मेडिकेयर पर निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में अवैध बिक्री के लिए राखी दवाइयां जप्त की दिन दवाइयां को नशे की पूर्ति के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है यह कार्रवाई नवदीप संधू, ड्रग्स कंट्रोल अधिकारी, लुधियाना-3 द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु की गई। ड्रग इंस्पेक्टर के ने बताया कि निरीक्षण के दौरान केमिस्ट शॉप से प्रेगाबालिन साल्ट युक्त चार प्रकार की एलोपैथिक दवाइयाँ स्टॉक में पाई गईं। हालांकि, फर्म द्वारा इन दवाइयों के खरीद संबंधी आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए, जो कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत अनिवार्य है। इस उल्लंघन को देखते हुए लगभग 23,408/- मूल्य की दवाइयों को मौके पर ही जब्त कर लिया गया।

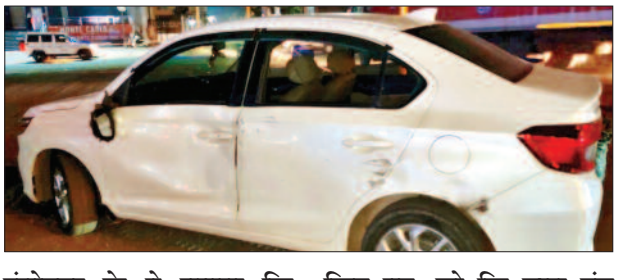

रूह से रूबरू

चारू नागपाल

क्या आम जनता चाहती है कि उन पर मिसाइलें गिरें?

क्या आम जनता कभी यह चाह करती है कि उनके घरों, स्कूलों और अस्पतालों पर बम और मिसाइलें गिरें? बिल्कुल नहीं। हर इंसान शांति, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन चाहता है। आम लोगों की सबसे बड़ी इच्छा होती है कि वे अपने परिवार के साथ सुरक्षित वातावरण में रहें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और स्वस्थ जीवन जी सकें। सरकारों का गठन इसी उद्देश्य से किया जाता है कि वे जनता की रक्षा करें, उनके अधिकारों की सुरक्षा करें और देश में शांति बनाए रखें। सरकारें जनता के विश्वास पर टिकी होती हैं, और उनका कर्तव्य होता है कि वे देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। लेकिन जब युद्ध जैसी परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर आम लोगों पर ही पड़ता है। युद्ध और हिंसा किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हैं। इससे केवल विनाश, दुख और असुरक्षा बढ़ती है। स्कूल, अस्पताल और घर जैसे स्थान, जो जीवन और आशा के प्रतीक होते हैं, जब निशाना बनते हैं, तो मानवता को गहरी चोट पहुँचती है। इसलिए आवश्यक है कि सरकारें संवाद, शांति और कूटनीति को प्राथमिकता दें, ताकि आम जनता सुरक्षित और भयमुक्त जीवन जी सके।

कानूनी बात - निशांत प्रभाकर के साथ

निशांत प्रभाकर, एडवोकेट

Encumbrance Certificate क्या होता है और क्यों जरूरी है?

संपत्ति खरीदते समय एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है—Encumbrance Certificate (EC)। यह प्रमाणपत्र बताता है कि किसी संपत्ति पर पिछले वर्षों में कोई कानूनी देनदारी, गिरवी या लेन-देन दर्ज हुआ है या नहीं।

Encumbrance Certificate स्थानीय पंजीकरण कार्यालय (Sub-Registrar Office) से प्राप्त किया जाता है। इसमें उस अवधि के दौरान संपत्ति से संबंधित सभी पंजीकृत लेन-देन का रिकॉर्ड दिखाई देता है। यदि संपत्ति पर बैंक का loan है या किसी प्रकार का registered charge है, तो वह EC में दिखाई देता है। इससे खरीदार को यह समझने में मदद मिलती है कि संपत्ति वास्तव में मुक्त है या उस पर किसी प्रकार की बाध्यता मौजूद है।

हालाँकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि EC केवल पंजीकृत लेन-देन को दिखाता है। कुछ दावे या विवाद ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी पंजीकृत न हों। इसलिए EC के साथ अन्य दस्तावेजों की जाँच भी आवश्यक होती है।

निष्कर्ष : Encumbrance Certificate संपत्ति के वित्तीय और कानूनी इतिहास की महत्वपूर्ण झलक देता है। संपत्ति खरीदने से पहले इसे जाँचना सुरक्षित निवेश का आवश्यक कदम माना जाता है।

लुधियाना में पूर्व कांग्रेस MLA को 2 साल की सजा: सरकारी काम में बाधा डालने के दोषी; लीगल एडवाइजर बोले- हायर कोर्ट जाएंगे

पंजाब/यूटर्न/17 मार्च। लुधियाना के होटल पार्क प्लाजा के मालिक और कांग्रेस के पूर्व विधायक जसबीर सिंह उर्फ जस्सी खंगूड़ा को सोमवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। लुधियाना के सेशन कोर्ट ने खंगूड़ा को साल 2008 के एक मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, सजा के ऐलान के बाद ही उन्हें कोर्ट से बेल भी मिल गई। उनके लीगल एडवाइजर का कहना है कि पूर्व विधायक की सजा के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील करेंगे। यह मामला डेहलों थाने में दर्ज सरकारी कर्मचारियों के साथ बदतमीजी और ड्यूटी में बाधा डालने से जुड़ा है। इसमें खंगूड़ा पर आरोप था कि उन्होंने ब्लॉक समिति चुनाव के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने संबंधित अधिकारियों की शिकायत के आधार पर धारा 353, 341, 332 के तहत डेहलों थाने में मामला दर्ज किया था।

हालांकि, वह केस खत्म हो गया था। इसके बाद साल 2017 में रिटर्निंग अफसर फकीर सिंह ने कोर्ट में केस दायर किया था।

इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान लुधियाना के एडिशन सेशन जज बरिंदर सिंह रमाणा की कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जस्सी खंगूड़ा को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई।

जानिए, जसबीर सिंह उर्फ जस्सी खंगूड़ा के बारे में

जस्सी खंगूड़ा लुधियाना के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और व्यवसायी हैं। वह पहले ब्रिटिश नागरिक थे। उन्होंने 2006 में भारत लौटकर अपनी नागरिकता छोड़ी और राजनीति में कदम रखा। इसके बाद 2007 में कांग्रेस के टिकल पर चुनाव लड़कर वह लुधियाना के किला रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बन गए। यह सीट पहले शिरोमणि अकाली दल का गढ़ मानी जाती थी। इसके बाद कांग्रेस ने 2012 के चुनाव में खंगूड़ा को दाखा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वह हार गए।

इसके बाद साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी (अअढ) जॉइन की थी। हालांकि, जब उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो वह मई 2024 में अअढ छोड़कर फिर से कांग्रेस में वापस आ गए।

पंजाब यूनिवर्सिटी में फायरिंग से हड़कंप, सतिंदर सरताज के शो से पहले सुरक्षा पर सवाल

अजीत झा

चंडीगढ़, यूटर्न, 17 मार्च। पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में मंगलवार को होने वाले गायक सतिंदर सरताज के कार्यक्रम से एक दिन पहले फायरिंग की घटना सामने आने से कैंपस में दहशत का माहौल बन गया। मंगलवार शाम करीब 5 बजे बॉटनी विभाग के पास पार्किंग क्षेत्र में स्कूटी सवार अज्ञात हमलावरों ने दो राउंड गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने सोपू से जुड़े एक्टिविस्ट जशन सिंह को निशाना बनाकर फायरिंग की। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद छात्र और

कर्मचारी घबरा गए और परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। डीएसपी दलबीर सिंह और सेक्टर-11 थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसपाल भुल्लर पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इसके अलावा क्राइम ब्रांच और ऑपरेशन सेल की टीमें भी जांच में जुट गई हैं। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए और पुलिस को घटनास्थल से दो खाली कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। डीएसपी दलबीर सिंह के अनुसार शुरूआती जांच में दो गोलियां चलने की पुष्टि हुई है और आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं।

कैंपस सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। सूत्रों के अनुसार यूनिवर्सिटी के एंट्री प्वाइंट्स पर सुरक्षा जांच की व्यवस्था होने के बावजूद हमलावर हथियार के साथ परिसर में दाखिल हो गए। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि पिस्तौल जैसे हथियार कैंपस के अंदर कैसे पहुंचे।

लुधियाना में किया शोरूम में करोड़ों के गबन की आशंका: ऑडिट में खुला राज,लेडी कैशियर ने UTR नंबर से डकारे ग्राहकों के पैसे ,पुलिस ने दर्ज किया मामला

पंजाब/यूटर्न/17 मार्च।लुधियाना के ऑटोमोबाइल सेक्टर में सामने आया यह मामला एक गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी का संकेत देता है, जिसमें भरोसे का दुरुपयोग कर बड़ी रकम का गबन किया गया। बताया जा रहा है कि ङ्क के शोरूम में तैनात कैशियर पूजा यादव ने अपने पद का फायदा उठाते हुए बिलिंग सिस्टम और रसीदों में हेराफेरी की। उसने ग्राहकों को फर्जी और डुप्लीकेट रसीदें जारी कीं और एक ही UTR नंबर का कई बार इस्तेमाल करके डिजिटल भुगतान का झूठा रिकॉर्ड तैयार किया। साथ ही, नकद भुगतान को

कंपनी के खाते में जमा करने के बजाय अपने पास रख लिया। यह धोखाधड़ी रूटीन ऑडिट के दौरान पकड़ी गई, जब अकाउंट्स विभाग ने ट्रांजेक्शन में गड़बड़ी देखी। आंतरिक जांच के बाद पूरा मामला सामने आया और 1 दिसंबर 2025 को पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अब थाना मोती नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। प्रारंभिक जांच के अनुसार गबन की राशि करोड़ों में हो सकती है, हालांकि सटीक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या इस मामले में कोई अन्य कर्मचारी शामिल था। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है और शोरूम प्रबंधन अपने पुराने रिकॉर्ड्स की दोबारा जांच कर रहा है।

लुधियाना में मंदबुद्धि युवक को 2 साल से बनाया बंधक: तरनतारन की संस्था ने छुड़ाया, मां तक पहुँचा बेटा, पुलिस ने किया मामला दर्ज

पंजाब/यूटर्न/17 मार्च। लुधियाना के गांव टिब्बा साहनेवाल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने अपने निजी स्वार्थ के लिए एक मंदबुद्धि व्यक्ति को पिछले दो साल से नरक भरी जिंदगी जीने पर मजबूर कर रखा था। आरोपी युवक से पशुओं का गोबर उठवाने और कूड़ा साफ करवाने जैसा बंधुआ मजदूरी का काम करवाता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब धन-धन बाबा रतन देव जी चैरिटेबल सोसाइटी तरनतारन के प्रधान जगजीत सिंह को इस जुल्म की गुप्त सूचना मिली। जगजीत सिंह ने बताया कि उन्हें खबर मिली थी कि गांव टिब्बा में भोलू खान नामक व्यक्ति ने एक बेसहारा मंदबुद्धि युवक को अवैध रूप से बंदी बनाकर रखा है। 22 फरवरी को संस्था के सदस्यों ने जब भोलू खान के डेरे पर रेड की तो वहां के हालात देख सबकी रूह कांप गई। आरोपी भोलू खान उसके बेटे रहमत अली और सदीक खान ने उस मासूम मंदबुद्धि को अपनी चंगुल में जकड़ा हुआ था और उससे जबरन मजदूरी करवा रहे थे। संस्था ने तुरंत उसे वहां से आजाद करवाया। आजाद करवाने के बाद युवक की पहचान इम्तियाज के रूप में हुई। संस्था ने उसकी फोटो और आपबीती सोशल मीडिया (फेसबुक) पर वायरल की। देखते ही देखते यह पोस्ट युवक की मां बीबी जेहर तक जा पहुँची। अपने कलेजे के टुकड़े को इस हाल में देख मां का रो-रोकर बुरा हाल है।जिसके बाद इसके शिकायत पुलिस को दी गई। थाना साहनेवाल पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर धाराएं: 127(2) इठर और 3(5) (बंधक बनाना और साजिश रचना के आरोप पर भोलू खान, रहमत अली और सदीक खान। पर मामला दर्ज कर लिया है।

मुख्यमंत्री ने आर्किटेक्ट संजय गोयल द्वारा डिजाइन किये गए नए अस्पताल भवन का किया उद्घाटन

चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को धूरी के सिविल अस्पताल में नवनिर्मित अस्पताल भवन

का उद्घाटन किया। इस नए भवन में 80 अतिरिक्त बेड हैं, जिसमें उप-मंडल अस्पताल का विस्तार और माँ और शिशु अस्पताल को शामिल किया गया है, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में वृद्धि होगी। लुधियाना स्थित डिजाइनेक्स आर्किटेक्टस के चीफ आर्किटेक्ट संजय गोयल ने कहा, ₹इस भवन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह कार्यक्षमता में कुशल और वास्तुकला की दृष्टि से मजबूत हो। केवल 18 महीनों में पूरी हुई यह इमारत आधुनिक डिजाइन सिद्धांतों और मरीज-केंद्रित योजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। भवन का डिजाइन चारों तरफ खुला है, जिसमें पर्याप्त पार्किंग की सुविधा, भरपूर प्राकृतिक रोशनी और बेहतर वेंटिलेशन उपलब्ध है, जिससे मरीजों और स्टाफ दोनों के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण सुनिश्चित किया गया है। इस परियोजना का प्रबंधन और निर्माण पंजाब मंडी बोर्ड के मार्गदर्शन में किया गया । उद्घाटन के दौरान, आर्किटेक्ट संजय गोयल ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से बातचीत की और भवन की नवीन विशेषताओं तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने में इसके योगदान पर प्रकाश डाला।

समाजवादी पार्टी ने राधेश्याम यादव को वार्ड-28 का प्रभारी बनाया

चंडीगढ़, यूटर्न, 17 मार्च। समाजवादी पार्टी चंडीगढ़ ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी गतिविधियों को विस्तार देने के उद्देश्य से प्रदेश कार्यकारिणी के सचिव राधेश्याम यादव को वार्ड नंबर-28 का नया प्रभारी नियुक्त किया है। पार्टी नेतृत्व ने यह निर्णय वार्ड की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। नई जिम्मेदारी के तहत राधेश्याम यादव अब मलोया गांव, ईडब्ल्यूएस कॉलोनी, सेक्टर-39 वेस्ट गुरुसागर भट्ठल कॉलोनी, ग्वाला कॉलोनी और कुम्हार कॉलोनी सहित वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी संगठन को मजबूत करने और गतिविधियों का संचालन करेंगे। पार्टी नेताओं के अनुसार राधेश्याम

यादव लंबे समय से समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं। उनकी सक्रियता और संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए ही पार्टी ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। बताया गया कि वर्ष 2021 के नगर निगम चुनावों के दौरान भी उन्होंने वार्ड-28 की आरक्षित सीट पर समाजवादी पार्टी की ओर से श्रीमती बिमला देवी को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा था।

संज्ञान आदेश को चुनौतीः निलंबित डीआईजी डीआईजी एचएस भुल्लर की याचिका पर सीबीआई को नोटिस

चंडीगढ़, यूटर्न, 17 मार्च। भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने अपने खिलाफ चल रहे मामले को लेकर सीबीआई कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी है। उन्होंने अदालत से अपील की है कि उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए लिया गया संज्ञान आदेश रद्द किया जाए। भुल्लर की याचिका में कहा गया है कि Central Bureau of Investigation द्वारा दायर चालान अधूरा है और मुकदमा शुरू करने से पहले आवश्यक सरकारी मंजूरी भी नहीं ली गई। उनके वकील एसपीएस भुल्लर ने दलील दी कि चार्जशीट में कई अहम दस्तावेज, जैसे सीएफएसएल रिपोर्ट, शामिल नहीं हैं, जिससे जांच अधूरी है। याचिका में यह भी कहा गया कि भुल्लर उस समय पंजाब में तैनात थे, इसलिए अभियोजन से पहले राज्य सरकार की अनुमति जरूरी थी। वहीं, कथित बिचौलिए कृष्णु शारदा ने भी संज्ञान आदेश को चुनौती दी है। अदालत ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 मार्च को तय की गई है। गौरतलब है कि 13 मार्च को अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया था, जबकि भुल्लर और शारदा को 16 अक्टूबर 2025 को रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

AI वीडियो में गोल्डन टेंपल में बेअदबीः कंकाल को पगड़ी पहना जूतों समेत परिक्रमा-लंगर हॉल में दिखाया; 7 लाख लोग देख चुके

चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च। अमृतसर स्थित गोल्डन टेंपल से जुड़ा एक कथित AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में एक कंकाल को पगड़ी पहनाकर मंदिर की परिक्रमा और लंगर हॉल में जूते पहने हुए दिखाया गया है, जिसे सिख मयार्दा के खिलाफ माना जा रहा है। इसको लेकर सिख समुदाय में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जांच शुरू कर दी है। एसजीपीसी सदस्य गुरचरण सिंह ग्रेवाल ने कहा कि वीडियो को मंगवाकर इसकी सत्यता और स्रोत की जांच की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। यह पहला मामला नहीं है जब अकके जरिए धार्मिक

भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा हो। इससे पहले भी ऐसे वीडियो सामने आए थे, जिनमें परिक्रमा में जूते पहनकर घूमना, कार ले जाना और आपत्तिजनक हरकतें दिखाना शामिल था। इन मामलों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन अमृतसर में 29 जनवरी को केस भी दर्ज किया गया था। वायरल वीडियो करीब 1 मिनट 36 सेकंड का है और इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं। अब एसजीपीसी की अकजांच कमेटी इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है।

चुनावी जिम्मेदारीः पंजाब के IAS-IPS अफसरों को दूसरे राज्यों में ड्यूटी

चंडीगढ़, यूटर्न, 17 मार्च। पंजाब के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया है। यह ड्यूटी लगभग दो महीने तक चलेगी।

जानकारी के अनुसार, पंजाब से 26 IAS और 7 IPS अधिकारियों को West Bengal, Kerala, Assam, Tamil Nadu और Puducherry में जनरल व सुरक्षा पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

IAS अधिकारियों के नामः अभिनव, अमित धाका, अमृत सिंह, अपनीत रायत, अरविंद

कुमार एम.के., दीप्ति उप्पल, घनश्याम थोरी, गुरिंदर पाल सिंह साहोता, गुरकिरात किरपाल सिंह, हरप्रीत सिंह सूदन, जोशी अजित बालाजी, कुलवंत सिंह, परमवीर सिंह, परमिंदर पाल सिंह, प्रयंक भारती, राहुल तिवारी, राजीव प्रशर, रामवीर, संदीप कुमार, शेना अग्रवाल, शौकत अहमद पर्रे, सोनाली गिरी, सैयद सेहरिश असगर, उमा शंकर गुप्ता, उपकार सिंह, वरुण रूजाम, विनेश सरंगल।

IPS अधिकारियों के नामः अखिल चौधरी, अलका मीणा, आशीष चौधरी, बाबूलाल मीणा, धरुव दहिया, कौस्तुभ शर्मा, एस. बूपति।

इन अधिकारियों को चुनाव आयोग के निदेर्शानुसार चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

60 लोगों ने मोबाइल मार्केट सेक्टर 22 में किया रक्तदान

चंडीगढ़, यूटर्न, 17 मार्च। अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरा करने हेतु निफा चंडीगढ़, श्री शिव कांवड़ महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा महामाई मनसा देवी चेरिटेबल भंडारा कमेटी एवं ब्लड बैंक गुरु हरकिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल, सोहाना के सहयोग से रक्तदान जागरूकता शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन कैपिटल फोटोज सेक्टर 22 चंडीगढ़ के चेयरमैन सुधार अमरजीत सिंह एवं मैनेजिंग डायरेक्टर विजय कुमार के कर कमलों द्वारा किया गया। उन्होंने लोगों का आव्हान किया इसमें कार्य में बढ़-चढ़कर भाग ले और एक स्वस्थ व्यक्ति का

इंसानी नैतिक और सामाजिक दायित्व बनता है कि वह हर समय स्वयं को रक्तदान के लिए तैयार रखे। हर स्वस्थ व्यक्ति को इसलिए भी रक्तदान करना चाहिए क्योंकि रक्त का कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

श्री शिव कावड़ महासंघ चैरिटेबल ट्रस्ट एवं निफा चंडीगढ़ के डायरेक्टर रमेश नारंग एवं प्रधान राकेश कुमार संगर ने बताया कि आजकल सभी अस्पतालों में रक्त की कमी है और रक्तदान का मकसद उन मरीजों की मदद करना है, जिनकी जिंदगी की डोर रक्त की कमी से कमजोर पड़ जाती है। आज रक्तदान शिविर में 60 लोगों ने रक्तदान किया। गया। इस अवसर श्री शिव कांवड़ महासंघ के लक्ष्मण सिंह रावत, संजोगिता, विनीत जगोता, राजेंद्र कौशल, गुलशन कुमार, दिव्या गुप्ता, शिवांजली, मुकेश बंसल एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रक्तदातों को प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर प्रोत्साहित किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष का राज्यसभा पहुंचना संगठन की शक्ति और राष्ट्रसेवा की प्रतिबद्धता का प्रतीकः जितेंद्र पाल मल्होत्रा

चंडीगढ़, यूटर्न, 17 मार्च। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल संगठन के लिए गौरव का विषय है, बल्कि राष्ट्रहित में उनके निरंतर समर्पण और अथक परिश्रम का सम्मान भी है। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संदेश

में कहा कि नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास और जनसेवा के नए आयाम स्थापित कर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष का उच्च सदन में पहुँचना निश्चित रूप से संगठन की विचारधारा और नीतियों को और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का संगठनात्मक अनुभव, दूरदर्शी नेतृत्व और जनकल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता राज्यसभा में नई ऊर्जा और सकारात्मक दिशा प्रदान करेगी। उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा और ठोस निर्णय लिए जाएंगे, जिससे देश के विकास को और गति मिलेगी। जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह नया दायित्व भारतीय लोकतंत्र को और सशक्त बनाएगा तथा जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कामना की कि वे अपने इस नए दायित्व में भी सफलता के नए आयाम स्थापित करें और राष्ट्र सेवा के पथ पर निरंतर अग्रसर रहें।

कॉस्मो मॉल के बाहर फिर चालू हुई एलईडी स्क्रीन, नगर परिषद की कार्रवाई पर उठे सवाल

बंद करवाने के कुछ दिन बाद ही दोबारा शुरू, 'एड माफिया' को संरक्षण की आशंका

जीरकपुर, यूटर्न, 17 मार्च। शहर में अवैध विज्ञापन बोर्डों और डिजिटल एलईडी स्क्रीन के खिलाफ नगर परिषद की कार्रवाई एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। कॉस्मो मॉल के बाहर लगी एलईडी स्क्रीन, जिसे हाल ही में बंद करवाया गया था, अब दोबारा चालू हो गई है। इससे शहर में ह्यएड माफियाह्न के खिलाफ प्रशासन की सख्ती पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यह एलईडी स्क्रीन नियमों के खिलाफ थी और इसे बंद कराया गया था, तो कुछ ही दिनों बाद इसके फिर से चालू हो जाने से साफ है कि कार्रवाई केवल औपचारिकता बनकर रह गई। लोगों के मुताबिक, यदि यह विज्ञापन डिस्प्ले अवैध है तो इसे पूरी तरह हटाया जाना चाहिए था।

सूत्रों के अनुसार, मीडिया में मामला उठने के बाद ही नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए एलईडी स्क्रीन को बंद कराया था। लेकिन अब इसके दोबारा चालू हो जाने से यह आशंका गहरा गई है कि अवैध विज्ञापन लगाने वालों को कहीं न कहीं संरक्षण मिल रहा है।

शहर के कई प्रमुख स्थानों पर लगे बड़े विज्ञापन बोर्ड और डिजिटल स्क्रीन लंबे समय से विवाद का विषय बने हुए हैं, लेकिन कार्रवाई अक्सर अधूरी नजर आती है। आमतौर पर नोटिस जारी करने, अस्थायी रूप से बंद कराने या औपचारिक जांच तक ही कार्रवाई सीमित रह जाती है और कुछ समय बाद हालात फिर पहले जैसे हो जाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे एलईडी स्क्रीन और बड़े विज्ञापन डिस्प्ले को लेकर एनएचएआई की स्पष्ट गाइडलाइंस हैं, जिनका उद्देश्य सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तेज रोशनी और चलती तस्वीरें वाहन चालकों का ध्यान भटका सकती हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में नियमों के विपरीत लगी स्क्रीन को हटाने के बजाय अस्थायी रूप से बंद करना और फिर चालू होने देना नियमों की अनदेखी माना जाएगा। अब देखना यह है कि नगर परिषद इस मामले में सख्त रुख अपनाती है या फिर यह मुद्दा भी कुछ दिनों की चर्चा के बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा।

> मेरे संज्ञान में नहीं था। मैं चेक करवा लेता हूं।
> — परविंदर सिंह भट्टी, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जीरकपुर

1 अप्रैल से फास्टैग वार्षिक पास शुल्क में होगा संशोधन

नई दिल्ली, यूटर्न 17 मार्च। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास की लागू फीस को मौजूदा 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये करने की घोषणा की है। बढ़ी हुई फीस 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। फीस में यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। उल्लेखनीय है कि 56 लाख से अधिक उपयोगकताओं के साथ, निजी वाहन मालिकों के बीच फास्टैग वार्षिक पास का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। संशोधित दर

वैध फास्टैग वाले पात्र गैर-व्यावसायिक वाहनों पर लागू होगी, जो राष्ट्रीय राजमार्गों और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे पर लगभग 1,150 टोल प्लाजा पर वार्षिक पास सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं। गौरतलब है कि फास्टैग वार्षिक पास से फास्टैग को बार-बार रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। एक बार का शुल्क भुगतान एक वर्ष की वैधता या 200 टोल प्लाजा को पार करने के लिए मान्य होता है। यह पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है। राजमार्ग यात्रा ऐप या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से एकमुश्त शुल्क का भुगतान करने के बाद वाहन से जुड़े मौजूदा फास्टैग पर वार्षिक पास दो घंटे के भीतर सक्रिय हो जाता है।

बाल भिक्षा रोकथाम हेतु जिला टास्क फोर्स द्वारा की गई चेकिंग

दलजीत अज्नोहा

होशियारपुर/यूटर्न, 17 मार्च। पंजाब सरकार द्वारा बाल भिक्षा की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट जीवनजोत-2 के तहत दसूहा के विभिन्न क्षेत्रों रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हाजीपुर चौक, ब्लग्गणा चौक में बाल भिक्षा रोकने हेतु रेड की गई और आम जनता को बाल भिक्षा के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया गया। जिला प्रोग्राम अधिकारी गगनदीप सिंह ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर के दिशा-निर्देशों और डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन के मार्गदर्शन में समय-समय पर चेकिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह चेकिंग

बाल कल्याण कमेटी की चेयरपर्सन के नेतृत्व में हरजीत कौर की टीम द्वारा जिला स्तरीय बाल भिक्षा रोकथाम टास्क फोर्स के साथ मिलकर की गई। इस दौरान हाजीपुर से 3 बच्चों को बाल भिक्षा से मुक्त करवाकर बाल कल्याण कमेटी, होशियारपुर के समक्ष पेश किया गया। कमेटी की ओर से बच्चों की काउंसलिंग की गई और उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें नारी निकेतन, जालंधर में दाखिल किया गया। बाल कल्याण कमेटी की चेयरपर्सन की ओर से आम जनता से अपील की गई कि यदि कोई बच्चा भीख मांगता या बाल मजदूरी करता हुआ दिखाई दे, तो इसकी सूचना बाल हेल्पलाइन 1098 पर दें, ताकि आपकी एक पहल किसी बच्चे की जिंदगी बदल सके। उन्होंने बताया कि 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जिला बाल सुरक्षा यूनिट, होशियारपुर से या बाल हेल्पलाइन 1098 पर फोन करके प्राप्त की जा सकती है।

बदलाव या ब्रॉडकास्ट? अमित शाह की मोगा रैली ने पंजाब को 2027 के लिए तैयार किया, लेकिन सुन कौन रहा है ?

एक ऐसी रैली जो वर्तमान से आगे की सोचती है

संदीप शर्मा, सम्पादक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की 'बदलाव रैली' को चार दिन बीत चुके हैं। लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया है और वह भी किस अंदाज में ! यह रैली तात्कालिक राजनीतिक फायदों के बारे में कम और 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों या शायद उससे भी आगे के लिए एक लंबी रणनीति बनाने के बारे में ज्यादा थी। बीजेपी को लंबे समय तक चलने वाले दांव खेलना पसंद है। इसका संदेश बहुत सोच-समझकर तैयार किया गया था, जिसमें कई परतें थीं और जो साफ तौर पर रणनीतिक था। इसमें पहचान की राजनीति, सुशासन के वादे और वैचारिक संकेतों का मिश्रण था। फिर भी, भीड़ जुटाने के इस दिखावे के पीछे एक गहरा सवाल छिपा है क्या यह 'बदलाव' पंजाब के अनोखे और जटिल सामाजिक ताने-बाने के साथ तालमेल बिठा पाता है ?

एक जानी-पहचानी पिच, लेकिन सीमाओं के साथ...पंजाब की आबादी के कुछ हिस्सों में, शाह की बयानबाजी खासकर धार्मिक धर्मांतरण के मुद्दे पर कुछ हद तक लोगों को प्रभावित करती है। धर्मांतरण-विरोधी कानून का वादा उस व्यापक राष्ट्रीय विमर्श की ही एक गूंज है जिसे भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ाती रही है। हालाँकि, पंजाब, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसा नहीं है। यहाँ का हिंदू मतदाता सिख संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। और सिखों के लिए भी धर्मांतरण एक मुद्दा है। इस पिच को कोई जबरदस्त प्रतिक्रिया नहीं मिली, बल्कि यह बस औसत दर्जे की ही रही। कई लोगों को यह किसी उधार ली गई पटकथा जैसी लगती है जानी-पहचानी तो है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ की अपनी नहीं है।

सिखों की प्रतिक्रिया: सतर्क, अगर आशंकित नहीं तो...कई सिखों के लिए, शाह का भाषण उत्साह जगाने के बजाय ज्यादा भौंहें चढ़ाता है। पंजाब की राजनीतिक मानसिकता ने लंबे समय से खुले तौर पर धार्मिक ध्रुवीकरण का विरोध किया है। धर्मांतरण पर दिया गया जोर भले ही उसे सुरक्षा के रूप में पेश किया गया हो पंजाब में अनावश्यक माना जा सकता है; क्योंकि यहाँ धार्मिक सह-अस्तित्व केवल एक आदर्श ही नहीं, बल्कि एक जीती-जागती हकीकत है सिवाय माझा क्षेत्र में होने वाले धर्मांतरण के मामलों के। क्या यह सब सुशासन के बारे में है, या फिर पंजाब के वैचारिक परिदृश्य को बदलने के बारे में? यह सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है गुरुद्वारों से लेकर लोगों के बैठक-कमरों तक, हर जगह गूंज रहा है।

किसान: वह वर्ग जो टस से मस नहीं हुआ...अगर कोई एक ऐसा वर्ग है जो इस सबसे लगभग अप्रभावित रहा है, तो वे हैं पंजाब के किसान। कृषि कानूनों और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों की छाया अभी भी राज्य में बीजेपी के किसी भी जनसंपर्क अभियान पर छाई हुई है। शाह की रैली, अपने बड़े पैमाने के बावजूद, इस भरोसे की कमी को सीधे तौर पर दूर करने में नाकाम रही। किसानों के लिए, ₹बदलावह्न सिर्फ.बयानबाजी नहीं है; यह नीतियों की याद से जुड़ा है। जब तक यह खाई नहीं भर जाती, रैलियों में भीड़ तो जुट सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि लोगों में पक्का भरोसा भी जागे।

धर्म-परिवर्तन का मुद्दा: रणनीति या जबरदस्ती?...शाह का यह दावा कि धर्म-परिवर्तन विरोधी बिल उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, शायद इस रैली का सबसे ज्यादा विचारधारा से भरा हिस्सा था। राष्ट्रीय स्तर पर, यह बीजेपी की मूल सोच से मेल खाता है। लेकिन पंजाब में, यह ऐसा लग सकता है जैसे किसी समस्या को ढूँढ़कर उसका हल निकाला जा रहा हो। राज्य में धर्म-परिवर्तन कभी भी चुनाव का मुख्य मुद्दा नहीं रहा है। इसे मुख्य मुद्दा बनाकर, बीजेपी शायद एक खास तबके में जोश भर दे लेकिन साथ ही, वह दूसरे लोगों को नाराज करने का जोखिम भी उठा सकती है, जो इसे जरूरी आर्थिक और खेती-बाड़ी से जुड़ी चिंताओं से ध्यान भटकाने की कोशिश मानते हैं।

2027: महत्वाकांक्षा और गणित का मेल...यह रैली आखिरकार 2027 तक पंजाब की राजनीति में एक छोटे खिलाड़ी से एक बड़ी ताकत बनने की बीजेपी की महत्वाकांक्षा को दिखाती है। बिहार जैसे राज्यों में पार्टी का सफर, जहाँ वह एक छोटे सहयोगी से एक बड़ी ताकत बन गई एक ऐसा मॉडल पेश करता है जिसे बीजेपी पंजाब में भी दोहराने की उम्मीद कर सकती है। लेकिन पंजाब में बने-बनाए मॉडल काम नहीं करते। यहाँ की राजनीति अचानक उठने वाली लहरों के बारे में कम, और धीरे-धीरे होने वाले बदलावों के बारे में ज्यादा है। बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ.अपनी ताकत दिखाने की नहीं है, बल्कि खुद को राज्य के सामाजिक-राजनीतिक माहौल में पूरी तरह से ढालने की है।

आखिरी बात...मोगा रैली कोई बड़ा मोड़ नहीं थी, बल्कि एक तरह की तैयारी थी, यह मंज़िल पर पहुँचने का नहीं, बल्कि इरादा जाहिर करने का संकेत था। शाह ने वही सुर छेड़े जिन्हें वह सबसे अच्छी तरह जानते हैं। सवाल यह है कि क्या पंजाब उस धुन पर थिरकने को तैयार है या फिर वह पूरी तरह से एक नया संगीत रचने वाला है।

हाईकोर्ट की टिप्पणी: मां के पास रह रही बच्ची की कस्टडी को अवैध नहीं कहा जा सकता

अजीत झा

चंडीगढ़, यूटर्न, 17 मार्च। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने छह माह की बच्ची की कस्टडी को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक किसी कानूनी आदेश के विपरीत स्थिति साबित न हो, तब तक मां के पास बच्ची की कस्टडी को अवैध या गैरकानूनी नहीं माना जा सकता।

जस्टिस रुपिंदरजीत चाहल की पीठ ने इस टिप्पणी के साथ बच्ची की कस्टडी दिलाने की मांग को लेकर उसके पिता द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मां बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक होती है और ऐसी स्थिति में बच्ची का मां के साथ रहना अवैध नहीं माना जा सकता।

हैबियस कॉर्पस याचिकाओं के दुरुपयोग पर चिंता...सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि बच्चों की कस्टडी से जुड़े विवादों में हैबियस कॉर्पस याचिकाओं का

सहारा लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जबकि यह असाधारण संवैधानिक उपाय है और इसे गार्जियनशिप संबंधी मामलों का विकल्प नहीं बनाया जा सकता।

अदालत ने कहा कि संरक्षकता से जुड़े मामलों में अदालत बच्चे के सर्वोत्तम हित, उसकी सुरक्षा, देखभाल और भविष्य से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तृत जांच करती है। इसके विपरीत हैबियस कॉर्पस याचिका में इस तरह की गहन जांच का प्रावधान नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग स्थायी कस्टडी तय करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

पिता ने मां पर लगाए थे लापरवाही के आरोप...मामले में पंचकूला निवासी एक व्यक्ति ने याचिका दाखिल कर अपनी छह महीने की बच्ची की कस्टडी मां से दिलाने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान बताया गया कि बच्ची का जन्म जुलाई 2025 में हुआ था। इसके बाद पत्नी घर छोड़कर मायके में रहने लगी और वापस नहीं लौटी।

पिता ने आरोप लगाया कि मां बच्ची की ठीक से देखभाल नहीं कर रही और उसका समय पर टीकाकरण भी नहीं कराया गया। इस संबंध में उसने बाल कल्याण समिति के समक्ष शिकायत भी दी थी, जिसके बाद बच्ची का टीकाकरण कराया गया।

क्या है हैबियस कॉर्पस...हैबियस कॉर्पस एक संवैधानिक उपाय है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया हो। यदि बच्चा अपने कानूनी अभिभावक के साथ रह रहा हो तो आमतौर पर इस आधार पर दायर याचिका स्वीकार नहीं की जाती।

साइबर क्राइम पर सख्ती, मामलों में आई कमी – मुख्यमंत्री

चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च।हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य में साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से काम कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र में बताया कि वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में साइबर क्राइम के मामलों में करीब 17% की कमी आई है। 2024 में 6054 मामलों के मुकाबले 2025 में यह संख्या घटकर 5000 रह गई। ठगी के मामलों में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। 2024 में 9804 मामलों के मुकाबले 2025 में 6324 मामले सामने आए, जो लगभग 36% की कमी दशार्ते हैं। वहीं

आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है— 2024 में 5156 गिरफ्तारियों के मुकाबले 2025 में 8093 गिरफ्तारियां हुई, यानी करीब 57% की वृद्धि। मुख्यमंत्री ने बताया कि साइबर अपराध से निपटने के लिए अलग साइबर क्राइम विभाग बनाया गया है। साथ ही 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे नए तरीकों पर भी नजर रखी जा रही है, जहां ठगी की रकम कई खातों में ट्रांसफर कर दी जाती है। पुलिस और बैंकों के समन्वय से ऐसी रकम को तुरंत होल्ड किया जाता है।

2024 में 27% राशि होल्ड की गई थी, जो 2025 में बढ़कर 40% हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि 1930 हेल्पलाइन और जीरो एफआईआर जैसी व्यवस्था से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। भविष्य में गोहाना, बहादुरगढ़ और सोनीपत में नए साइबर थाने खोले जाएंगे। बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्यूल ओटीपी सिस्टम लागू करने जा रही है, जिससे साइबर ठगी पर और प्रभावी रोक लगाई जा सके।

सिविल अस्पताल ढकोली में जेबकतरी गैंग का भंडाफोड़, बच्चों को ढाल बनाकर करते थे वारदात

चार महिलाएं गिरफ्तार, 22,500 रुपये बरामद; भीड़भाड़ में लोगों को बनाती थीं निशाना

जीरकपुर , यूटर्न, 17 मार्च। सिविल अस्पताल ढकोली में हुई जेबकतरी की वारदात में पुलिस जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आरोप है कि महिला आरोपी अपने साथ छोटे बच्चों को गोद में लेकर अस्पताल में घूमती थीं, ताकि किसी को उन पर शक न हो। इसी आड़ में वे भीड़भाड़ का फायदा उठाकर लोगों को निशाना बनाती थीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार करनैल सिंह अपने बेटे जगतर सिंह के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। वह पर्ची कटवाने के लिए लाइन में खड़े थे। इसी दौरान

चार महिलाएं उनके आसपास आकर खड़ी हो गईं और कुछ ही मिनटों में उनकी जेब से 30 हजार रुपये निकालकर भीड़ में गायब हो गईं।

घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार महिलाओं की पहचान नेहा पत्नी रितेश, नंदिनी पत्नी देव, रीमा पत्नी शिव और दिशा पत्नी रोहन के रूप में हुई है। सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव की रहने वाली हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 22,500 रुपये भी बरामद किए हैं।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह गैंग संगठित तरीके से सक्रिय है और अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की वारदातों को अंजाम देने की आशंका है। आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड लिया जाएगा, ताकि पूछताछ के दौरान और मामलों का खुलासा हो सके।

चंडीगढ़ पुलिस के खिलाफ ढउअ में पहुंची शिकायत: मिलीभगत और सबूत दबाने के आरोप, 3 हफ्ते बाद FIR, स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग

चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च। चंडीगढ़ के सेक्टर-36ए में प्रॉपर्टी विवाद से जुड़े एक गंभीर मामले ने नया मोड़ ले लिया है। 67 वर्षीय निवासी स्वर्णजीत सिंह सराओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए चंडीगढ़ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी (PCA) में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि सेक्टर-36 थाना पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए न केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, बल्कि सबूतों से छेड़छाड़ कर जांच को कमजोर किया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने 25 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को संभावित हमले की चेतावनी दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 28 अगस्त 2024 को कुछ लोग उनके घर में जबरन घुस आए, मारपीट की और उनकी बेटी को हथौड़े से धमकाया। मौके पर पहुंची पीसीआर टीम को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हथियार तक निकालने पड़े। इसके बावजूद, तत्काल एफआईआर दर्ज नहीं की गई और मामले को सामान्य झगड़ा बताकर डीडीआर में दर्ज किया गया। लगभग तीन सप्ताह बाद 13 सितंबर 2024 को एफआईआर दर्ज हुई। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि महत्वपूर्ण फोटो सबूत और गवाहों को चार्जशीट में शामिल नहीं किया गया। अब उन्होंने स्वतंत्र जांच, दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल 2026 को होगी।

जीरकपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर: हादसे का CCTV फुटेज आया सामने; बाल-बाल बचे गाड़ी सवार

चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च। जीरकपुर के PR-7 एयरपोर्ट रोड पर स्थित छत लाइट प्वाइंट के पास मंगलवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि कार सवार सुरक्षित बच गए और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हादसा उस समय हुआ, जब मोहाली की ओर से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली और पटियाला की तरफ से आ रही कार आमने-सामने आ गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली का अगला हिस्सा कार के पिछले हिस्से में जा घुसा। दुर्घटना में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे की फुटेज अब सामने आई है, जिसमें टक्कर की भयावहता साफ देखी जा सकती है। स्थानीय लोगों के अनुसार, इस स्थान पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से यहां ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

पंजाब में दाखिले-नौकरियों में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को वेटेज: 75% प्रदर्शन, 25% प्रवेश परीक्षा के अंक रहेंगे, ग्रेड के हिसाब से नौकरी

पंजाब/यूटर्न/17 मार्च। पंजाब सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में दाखिले में अधिक अवसर मुहैया करवाने के लिए नई स्ट्रेटजी बनाई है। अब उनके ग्राउंड में दिखाए गए प्रदर्शन को प्राथमिकता मिलेगी। उनके नौकरी की राह में जिला स्तर से लेकर इंटरनेशनल मुकाबलों में उनका अहम भूमिका निभाएगा। इसके लिए पंजाब स्टेट पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्सपर्सन जारी की है। पॉलिसी में सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर लागू होगी। पुरानी 1988 की खेल भर्ती भी जहां-जहां अंतर है, नई नीति उसे ओवरराइड कर देगी। नई पॉलिसी के मुताबिक खेल उपलब्धियों को 75 प्रतिशत वेटेज और प्रवेश परीक्षा को 25 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा, जबकि सभी विज्ञापित पदों के लिए खेल विभाग द्वारा खेल ग्रेडेशन और स्कोरिंग अनिवार्य कर दी गई है। अंकों का लाभ केवल तभी मिलेगा जब उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम क्वालीफाइंग अंक प्राप्त कर लेगा। खेल ग्रेड के आधार पर नौकरी के लिए सरकार ने 4 ग्रुप तय किए हैं। ग्रेड अ और इ वाले ग्रुप अ, इ, उ और ऊकी नौकरियों के लिए पात्र होंगे। जबकि ग्रेड उ वाले ग्रुप उ और ऊकी नौकरियों के लिए पात्र हैं। ग्रेड ऊकेवल ग्रुप ऊ की नौकरियों के लिए पात्र हैं। 2023 की खेल नीति के अनुसार खेलों (एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल आदि) के खिलाड़ियों को शैक्षणिक, तकनीकी और मेडिकल संस्थानों में दाखिले के समय वरीयता देने का प्रावधान था, लेकिन अब यह प्रदर्शन पर निर्भर करेगा।

ठगी के आरोपी स्लिमिंग-क्लिनिक लुधियाना के डायरेक्टर फरार: पनाह देने वाला गिरफ्तार, 4 निदेशकों पर दिल्ली के डॉक्टर ने दर्ज कराया केस

पंजाब/यूटर्न/17 मार्च।लुधियाना के सराभा नगर स्थित सिंगला स्लिमिंग क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े ठगी मामले में नया मोड़ सामने आया है। क्लिनिक के डायरेक्टर और आरोपी निखिल सिंगला को पुलिस से बचाने के आरोप में हैबोवाल के न्यू दीप नगर निवासी अशोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, निखिल सिंगला पर दिल्ली के डॉक्टर अरमान थापर से धोखाधड़ी करने का आरोप है। इस संबंध में 14 फरवरी को थाना डिवीजन नंबर-5 में एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले में डॉ. सुशील सिंगला, डॉ. अंजू सिंगला, निखिल सिंगला और समृद्धि सिंगला को नामजद किया गया है, जबकि निखिल अभी फरार है। जांच में सामने आया कि अशोक सिंह ने आरोपी को अपने घर में पनाह दी थी। पुलिस ने सूचना के आधार पर रेड की, लेकिन छापेमारी से पहले ही निखिल वहां से फरार हो गया। इसके बाद पुलिस ने अशोक सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने क्लिनिक से फ्रेंचाइजी लेने के लिए निवेश किया था, जिसमें 18 महीने में रकम लौटाने का वादा किया गया था। लेकिन उन्हें मुनाफा नहीं हुआ, बल्कि करीब 2.14 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। साथ ही, उन्हें महंगी कीमत पर मशीनें खरीदने के लिए मजबूर किया गया, जो बाजार में सस्ती उपलब्ध थीं। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और मामले की जांच जारी है।

पंजाबी सिंगर बब्बू मान पुलिस के 'ब्रांड एंबेसडर': बोले- गानों में ही अच्छे लगते हैं हथियार-परचे, जेल में कोई अचार भी नहीं देता है

एक 'पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर' और ब्रांड एंबेसडर के तौर पर पेश करते हुए युवाओं को गन

पंजाब/यूटर्न/17 मार्च। पंजाबी सिंगर बब्बू मान गन कल्चर व हथियारों को प्रमोट करने वाले कई गीत गा चुके हैं। हालांकि अब वो ऐसे गीतों को गाने से परहेज करते हैं। बब्बू मान तो अब युवाओं को हथियारों से दूर देने के लिए प्रेरित करने लगे हैं।

हाल ही में उन्होंने मलेरकोटला के लाइव शो में युवाओं को यहां तक कह दिया कि हथियार-परचे गानों में ही अच्छे लगते हैं, जेल में कोई अचार भी नहीं देता। पंजाब पुलिस ने इस क्लिप को अपने सोशल मीडिया पेज पर अपलोड करके बब्बू मान को ब्रांड एंबेस्डर के तौर पर पेश किया है। पुलिस ने मान को कल्चर से दूर रहने का संदेश दिया है। पुलिस का मकसद युवाओं को यह समझाना है कि अपराध की राह पर चलने का अंजाम सिर्फ बबार्दी है। बब्बू मान ने युवाओं से अपील की कि वे अपनी ताकत को शिक्षा और रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ें। उन्होंने कहा कि असली बहादुरी समाज के लिए एक मिसाल बनने में है, न कि अपराध की दुनिया में नाम कमाने में। पंजाब पुलिस ने इस क्लिप के जरिए 'एंटी-गन कल्चर' मुहिम को प्रमोट करने की कोशिश की है, ताकि राज्य के युवा अपराध की चमक-धमक से प्रभावित होकर अपना भविष्य न बिगाड़ें।

घर से 376 पोस्त के पौधे बरामद, कथित आरोपी काबू

-चरणजीत सिंह चन्न-

जगरांव/यूटर्न/17/मार्च। लुधियाना देहाती पुलिस के थाना दाखा की पुलिस ने नशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घर में लगाए गए भारी मात्रा में पोस्त (अफीम) के पौधे बरामद किए हैं। जांच अधिकारी ए.एस.आई. इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। सूचना मिली थी कि हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदर निवासी तलवंडी खुर्द ने अपने घर की खाली जगह में पोस्त के पौधे लगाए हुए हैं। पुलिस द्वारा मौके पर की गई रेड के दौरान 376 पोस्त के पौधे बरामद किए गए और कथित आरोपी को काबू कर लिया गया। पुलिस द्वारा मामले में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

वार्ड नंबर 4 में विकास की नई शुरूआत

बुजुर्ग महिला ने शुभारंभ कर शुरू करवाया गलियों का निर्माण कार्य

-चरणजीत सिंह चन्न-

जगरांव/यूटर्न/16/मार्च। वार्ड नंबर 4 में विकास कार्य लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं। इलाके के पार्षद अमरजीत सिंह मालवा द्वारा लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई गलियों के निर्माण कार्य की शुरूआत करवाई गई। इस मौके पर एक भावुक और प्रेरणादायक दृश्य देखने को मिला, जब बुजुर्ग महिला सुरिंदर कौर ने टक्कर लगाकर सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह निर्माण कार्य कुलदीप सिंह घागू के घर से लेकर बिल्लू बिजली वाले के घर तक किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पार्षद अमरजीत सिंह मालवा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गली के निर्माण पर लगभग 4 लाख रुपये की लागत आएगी। इसके साथ ही बाला जी बर्तन स्टोर से मलका बुटीक तक दूसरी गली का निर्माण भी किया जाएगा, जिस पर करीब 12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोनों गलियों का निर्माण कार्य 7 दिनों के भीतर पूरा कर लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा। इलाके के लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। इस मौके पर नछत्तर सिंह, अमरजीत सिंह बिल्लू, मनजीत सिंह, अजमेर सिंह हैप्पी, कुलवंत कौर, छिंदरपाल सिंह, दविंदर सिंह और जसविंदर सिंह सहित अन्य स्थानीय निवासी भी उपस्थित रहे। यह परियोजना वार्ड नंबर 4 में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।

Kirti Suresh

क्या ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी रात भर चले हमले में मारे गए?

चंडीगढ़/यूटर्न/17 मार्च। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान पर इजराइल द्वारा रातभर किए हमलों में जिन लोगों को निशाना बनाया गया, उनमें ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी भी शामिल थे। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह अभी भी साफ नहीं है कि ईरान की सत्ता-व्यवस्था के एक शीर्ष व्यक्ति लारीजानी हमले में मारे गए या घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हुई। इजराइल के रक्षा मंत्री, इजराइल काट्ज ने भी दावा किया है कि लारीजानी मारे जा चुके हैं। लारीजानी, जो पहले परमाणु वातार्कार रह चुके हैं और वर्तमान में ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के रूप में कार्यरत हैं, उन्हें ईरान की सत्ता संरचना में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। यदि उनकी मृत्यु की पुष्टि हो जाती है, तो सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद लारीजानी सबसे वरिष्ठ ईरानी अधिकारी होंगे जिनकी मृत्यु हुई है; खामेनेई की मृत्यु युद्ध के पहले ही दिन हो गई थी। लारीजानी, अली खामेनेई के एक करीबी सहयोगी थे।

आखिरी बार तेहरान में देखें गए

रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें आखिरी बार शुक्रवार को तेहरान में 'कुद्स दिवस' की रैलियों के दौरान सार्वजनिक रूप से देखा गया था। उसी दिन बाद में, अमेरिका ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े 10 व्यक्तियों की सूची के हिस्से के रूप में, लारीजानी सहित वरिष्ठ ईरानी सैन्य और खुफिया अधिकारियों के बारे में जानकारी देने पर 10 मिलियन डॉलर तक का इनाम देने की घोषणा की थी।

मिलिशिया नेता की मृत्यु को स्वीकार नहीं किया

कई इजराइली मीडिया आउटलेट्स ने यह भी बताया कि इन हमलों में बसीज प्रतिरोध बल के प्रमुख गुलामरेजा सुलेमानी और बसीज के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाया गया था; इन हमलों के परिणामों का अभी भी आकलन किया जा रहा है। हालाँकि, ईरान ने इस मिलिशिया नेता की मृत्यु को तत्काल स्वीकार नहीं किया।

ईरानी मीडिया ने लारीजानी का बयान जारी किया

इस बीच, ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने मंगलवार को लारीजानी के नाम से एक बयान जारी किया, जिसमें ईरान के सुरक्षा प्रमुख ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कड़ी आलोचना की। बयान में कहा गया, 47 साल पहले, ईरान की इस्लामी क्रांति में लोगों की जीत की पूर्व संध्या पर, पहलवी शासन के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि सड़कों पर उमड़ी विशाल भीड़ के नारे लगाने की आवाज असली नहीं, बल्कि एक टेप रिकॉर्डिंग की आवाज थी! अब ट्रम्प ईरानी शहरों में लाखों की संख्या में हो रही अमेरिका-विरोधी और इजराइल-विरोधी सभाओं के बारे में कहते हैं कि ये तस्वीरें 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) द्वारा बनाई गई हैं। इसमें आगे कहा गया, ईरानी लोगों की, एपस्टीन द्वीप के बचे-खुचे अवशेषों पर ऐतिहासिक जीत करीब है।

लारीजानी की इस्लामी दुनिया से अपील... ये रिपोर्टें ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव के उस संदेश के एक दिन बाद आईं, जिसमें उन्होंने मुस्लिम दुनिया से कहा था कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ बना हुआ है। लारीजानी ने इस बात पर निराशा जताई कि जब ईरान पर हमला हुआ, तो उन्हें मुस्लिम-बहुल देशों से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। उन्होंने सोमवार को कहा, ईरान पर एक विश्वासघाती अमेरिकी-जायोनी हमला हुआ। यह हमला बातचीत के दौरान हुआ था और इसका मकसद ईरान को खत्म करना था। इस हमले के कारण इस्लामी क्रांति के महान और आत्म-बलिदानी नेता के साथ-साथ कई नागरिकों और सैन्य कमांडरों को शहादत देनी पड़ी।

नगर निगम सख्त: नियम तोड़ने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, ऑन-द-स्पॉट चालान के निर्देश

चंडीगढ़, यूटर्न, 17 मार्च। शहर में नागरिक नियमों के सख्त पालन और उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम चंडीगढ़ ने प्रवर्तन व्यवस्था को और तेज करने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर डॉ. हिमांशु गुप्ता ने मंगलवार को जूनियर इंजीनियरों, सैनिटरी इंस्पेक्टरों और एन्फोर्समेंट इंस्पेक्टरों के साथ बैठक कर शहर भर में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में जॉइंट कमिश्नर ने स्पष्ट कहा कि नगर निगम नियमों के उल्लंघन के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ बिना किसी ढील के कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने फील्ड स्टाफ को सतर्क रहने और मौके पर ही चालान करने के निर्देश दिए, ताकि नियम तोड़ने वालों में सख्त संदेश जाए। साथ ही सभी सेक्टरों में नियमित निरीक्षण बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। डॉ. हिमांशु गुप्ता ने कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल, सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाना, सड़कों के किनारे निर्माण मलबा फेंकना, अवैध रेहड़ी-फड़ी लगाना, बिना अनुमति के विज्ञापन बोर्ड लगाना, दीवारों पर पोस्टर चिपकाकर गंदगी फैलाना और लावारिस या खड़े छोड़े गए वाहन जैसे उल्लंघन नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सबूतों के अभाव में दुष्कर्म केस में आरोपी बरी

भूपिंदर सागर

मोहाली, यूटर्न, 17 मार्च। दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में जिला अदालत ने पर्याप्त सबूत न होने के कारण आरोपी को बरी कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा, जिसके चलते आरोपी को संदेह का लाभ दिया गया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों गुरप्रीत सिंह भट्टी और राम धीमान ने दलील दी कि शिकायतकर्ता के आरोप तथ्यों और साक्ष्यों पर खरे नहीं उतरते।

उन्होंने अदालत को बताया कि फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की रिपोर्ट में भी आरोपी की संलिप्तता साबित नहीं हुई। इसके अलावा गवाहों के बयानों और प्रस्तुत साक्ष्यों में कई विरोधाभास सामने आए, जिससे शिकायतकर्ता के आरोपों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हुए। मामले के अनुसार, वर्ष 2023 में मोहाली निवासी एक युवती ने हरियाणा के रहने वाले अपने पति के खिलाफ वूमन सेल थाने में दुष्कर्म और मारपीट का केस दर्ज कराया था।

दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर हुई थी और वर्ष 2022 में दोनों ने विवाह कर लिया था। करीब तीन साल तक चले ट्रायल के बाद अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में असफल रहा है।

PM किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसान रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

बिना किसान आईडी नहीं मिलेगी अगली किस्त, CSC केंद्रों पर फ्री में बन रही आईडी

बठिंडा, 17 मार्च (सोनू टुटेजा)। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनकी किसान आईडी (किसान रजिस्ट्री) बनी होगी। डिप्टी कमिश्नर बठिंडा श्री राजेश धीमान ने बताया कि भारत सरकार के निदेशों के अनुसार अब योजना का लाभ लेने के लिए किसान रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन वाले किसानों को अगली किस्त जारी नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी सांझ सेवा केंद्रों (CSC) पर किसान आईडी बिल्कुल मुफ्त बनाई जा रही है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपने नजदीकी उरउ केंद्र पर जाकर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डॉ. हरबंस सिंह ने कहा कि किसान इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और समय रहते अपनी किसान आईडी बनवाएं, ताकि योजना का लाभ बिना किसी रुकावट मिलता रहे।

संपर्क के लिए अधिकारी

महेश इंदरपाल सिंह (नोडल ऑफिसर) - 8872100112,दविंदर सिंह संधू (APPO, तलवंडी साबो) -8283000860
हरजसपाल शर्मा (AO, बठिंडा/नथाना) -9780242923,भारत भूषण (अड, रामपुरा/मौर) -9478548373
हरदीप सिंह (AO, फूल) - 9464071825, मनोज कुमार (अड, संगत) - 9872552742

Owner, Publisher, Printer: - Komal Sharma, Printed by DB Corp LTD VPO Hamira, Distt Kapurthala-144601 (PB), Published by: House No 68, New Sarabha Nagar, VPO Daad, Ludhiana (PB) - 142022, Editor: Sandeep Sharma
तमाम प्रकाशित सामग्री के चयन व संपादन हेतु आरबीएक्ट के तहत जिम्मेवार।
Contact - +91 9814295372